समसामयिक राजनय में अवपीड़न और प्रत्यायन : जिम्बाब्वे संकट में ब्रितानी - अमेरिकी रणनीति का एक अध्ययन

एम० फिल० उपाधि के लिए
प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध

बिनोद कुमार

राजनय अध्ययन संभाग
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली - ११००६७

१९८४

विषय सूची

प्रस्तावना -- 3

अध्याय : 1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : रोडेशिया का राजनीतिक विकास 6

अध्याय : 2

रोडेशिया के घटनाक्रम में अवरोध का प्रयोग 21

अध्याय : 3

प्रत्यायन का काल 40

अध्याय : 4

निष्कर्ष 70

संदर्भ सूची 79-84

प्रस्तावना

औपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो दौर चला, वह वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्द्ध में और भी तेज हो गया । दुनिया के गुलाम देशों ने परतंत्रता की जंजीर को तोड़कर नये राष्ट्रों का स्वरूप लिया जिसमें मूल निवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला । इस आत्मनिर्णय की कड़ी में जिम्बाब्वे ने भी 1980 में विदेशी अल्पमत गोरी सरकार की बुनियाद को नष्ट कर डाला । जिम्बाब्वे वासियों को आत्म-निर्णय के अधिकार को हासिल करने के लिए न केवल ब्रितानी सरकार से लड़ना पड़ा बल्कि जिम्बाब्वे में बसे ब्रितानी अल्पसंख्यक गोरों की सरकार से भी लड़ना पड़ा । फलतः स्वतंत्रता प्राप्त करने में लंबा समय लगा और दो औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ना स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिम्बाब्वे एक अलग स्थान रखता है ।

1965 में जिम्बाब्वे की समस्या विश्व रंगमंच पर उभर कर सामने आ गयी । जब वहाँ बसे अल्पमत गोरों की सरकार ने "स्वतंत्रता की एक-पक्षीय घोषणा" की । इस घोषणा के अनुसार श्वेतवासी राजनीतिक एवं आर्थिक रू प से स्वतंत्र हो गये तथा अपने स्वार्थपूर्ण हितों के लिए अफ्रीकी मूल निवासियों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से शोषण करने लगे । इस शोषण के विरुद्ध अफ्रीकावासियों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़ा ।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध में समसामयिक राजनय में अवपीड़न एवं प्रत्यायन के संदर्भ में ब्रितानी एवं अमेरिकी रणनीति का जिम्बाब्वे के संकट के परिप्रेक्ष में अध्ययन किया गया है । जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबे अवपीड़न एवं प्रत्यायन से गुजरना पड़ा । इस स्वतंत्रता-संग्राम में ब्रितानी एवं अमेरिकी भूमिका को समझने के लिए जिम्बाब्वे

के राजनीतिक विकास को जानना आवश्यक है । अतः प्रथम अध्याय में जिम्बाब्वे के राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास का अध्ययन परतंत्र बनाने की प्रक्रिया से लेकर स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा 1965 तक किया गया है ।

"स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" के बाद ही यहाँ अवपीड़न शुरू हो गया । पर यह अवपीड़न सैनिक न होकर आर्थिक अवपीड़न रहा । आर्थिक अवपीड़न का प्रयोग तथ्ये अर्थों में नहीं किया गया । इसका उल्लंघन बड़े पैमाने पर हुआ है । तेलों का आयात विदेशी कंपनियों से छिपे रूप से होता रहा । यूरोप के कई देश इस उल्लंघन में शामिल थे । अमेरिका ने तो कांग्रेस द्वारा "बायड संशोधन" पारित करवा लिया जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका जिम्बाब्वे से कई मुख्य खनिज जैसे क्रोम, निकल आदि का आयात करने लगा तथा आर्थिक प्रतिबंध से छुटकारा पा लिया । इन सब तथ्यों का सर्वेक्षण दूसरे अध्याय में किया गया है ।

1974-75 की अवधि में दक्षिणी अफ्रीका में कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जो जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने लगीं । पुर्तगाल उपनिवेश का स्वतंत्र होना मुख्य घटना थी । एंगोला एवं मोजाँबिक की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका जो वर्षों से दक्षिण अफ्रीका की राजनीति से अलग था, सक्रिय रूप से शामिल हो गया । हेनरी किसींजर का "शमनागमन का राजनय" शुरू हो जाता है । इस समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक समझौता एवं संधि-वार्ता का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा जिसमें प्रत्यायन का काफी बोलबाला रहा, चाहे वह विक्टोरिया फॉल ब्रिज वार्ता हो या जेनेवा संधि वार्ता, चाहे सुसाका घोषणा हो या लैंकास्टर हाउस सम्मेलन । इसका विस्तृत अध्ययन तृतीय अध्याय में किया गया है । और अंतिम अध्याय में इन सारे तथ्यों के आधार पर ब्रितानी एवं अमेरिकी राजनय को अवपीड़न एवं प्रत्यायन के संदर्भ

में समझने की कोशिश की गयी है ।

इस विषय पर काम करने के लिए मैं अपने निर्देशक श्री विजय वंबोलकर का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण निर्देशन एवं सहयोग देकर मुझे प्रोत्साहित किया । इस लघु शोध-प्रबंध को पूरा कराने में डा० पुष्पेश पंत की जितनी सराहना की जाय, कम है । उनके मूल्यवान निर्देशन, सुझाव एवं सहयोग के लिए मैं सदा कृतज्ञ रहूँगा । प्रो० सतीश कुमार का भी मैं आभारी हूँ जो समय समय पर सहयोग एवं प्रोत्साहन देकर मुझे लाभान्वित करते रहे ।

इसके अलावा मेरे अनेक मित्रों ने, विशेषकर गोलक, सुदर्शन, सतीश, अरुण, रवि, रामनिवास, मिथिलेश, प्रमोद, अरविंद एवं नागेंद्र ने जो सहयोग दिया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । और अंत में सप्रू हाउस पुस्तकालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कर्मचारीगण भी अपनी सहायता के लिए धन्यवाद के पात्र हैं ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नयी दिल्ली-110067

:विनोद कुमार:

मई, 1984

अध्याय- I

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : रोडेशिया का राजनैतिक विकास

जिम्बाब्वे, जो स्वतंत्रता के पूर्व रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, 1923 में ब्रिटेन का उपनिवेश बना । 1923 के पहले रोडेशिया शाही-फरमान ।रायल चार्टर। के अधीन व्यापारिक कंपनी द्वारा शासित था। यहाँ लोबेंगुला का माताबेला साम्राज्य ब्रितानी प्रभाव का क्षेत्र था जिससे खनन एवं खनिज अधिकार संबंधी कई रियायतें, 1880 के अंतिम दशाब्द में ब्रिटेन ने प्राप्त कर ली थीं । ब्रिटिश साहसिक, उद्यमी व्यापारी सेसील रोडेस ने साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक नीतियों का अनुसरण किया था और पुरस्कारस्वरूप 1889 में उसे ब्रितानी सरकार द्वारा यह भूभाग उसकी दक्षिण अफ्रीकी कंपनी के लिए प्रदान किया गया ।[1]

मातोनालैंड पर आक्रमण एवं आधिपत्य एक राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्य से किया गया । डेविड लिविंगस्टन जैसे अन्वेषक एवं धर्म प्रचारक ने यूरोप में इस लोकप्रिय भ्रम की आधारशिला रखी कि "काला महाद्वीप" के अफ्रीका वासी लड़ाकू तथा जंगली आदिवासी हैं जो विकास की सीढ़ी से कई कदम पीछे हैं । अफ्रीका में सभ्यता के लिए यूरोपवासी द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक है तथा धर्म की आवश्यकता है । धर्म के आदमी ।जो अधिकतर अनैतिक एवं बेईमान थे। मातोनालैंड एवं उत्तर के क्षेत्र में सेसील रोडेस की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति से अलग नहीं थे ।[2]

1-के० यंग : रोडेशिया एंड इंडीपेंडेंट - ए स्टडी इन ब्रिटिश कोलोनियल पॉलिसी ।लंदन। 1967, पृ० 25

2-डी० मार्टिन एंड फिलिप जॉनसन : द स्ट्रगल फार जिम्बाब्वे - द चिमरेंगा वार ।लंदन। 1981, पृ० 36

1884-85 के बर्लिन सम्मेलन में डेविड लिविंगस्टन के "लोकप्रिय भ्रम" को एक नैतिक तर्क की प्रतिष्ठा प्रदान की गयी । फ्रांस ने तो यहाँ तक कह डाला कि यह एक "सभ्यता का मिशन" है । बेशक यह अफ्रीका को उपनिवेश बनाने की एक साजिश थी । बर्लिन सम्मेलन ने आक्रामकों, साहसिकों तथा धनलोलुप व्यक्तियों के लिए दरवाजा खोल दिया । इस सम्मेलन ने यह भी इंगित कर दिया कि यूरोपीय शासन सम्प्रभुता स्थापित करने से पहले इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेना आवश्यक है । इस निर्णय ने अफ्रीका में औपनिवेशिक प्रसार की गति को और तीव्र कर दिया । इस दौर में यूरोपियनों ने अपने आप को परिमोचक करार दिया । वस्तुतः वे दास व्यापारी थे वे जिन्होंने इस महाद्वीप की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों एवं स्वतंत्रता को समाप्त कर अपने आप को और अधिक धनवान बनाया ।[3]

1836 और मातोनालैंड पर आक्रमण के बीच कई संधियाँ माताबेला के राजा-- मजेलीकाजी तथा उसके पुत्र लोबेंगुला-- के साथ की गयीं । प्रथम संधि 1836 में मजेलीकाजी के दूत एवं ब्रितानी सरकार के प्रतिनिधि सर बैंजामिन डी0 अरबन के बीच हुई । इसके साथ ही धीरे-धीरे और कई संधियाँ हुई जैसे 1853 की संधि, 30 जुलाई 1887 की ग्रोबलर संधि (लोबेंगुला एन0 पीट ग्रोबलर के बीच), मोफत संधि (11 फरवरी, 1888 में) लोबेंगुला एवं जॉन मोफत के बीच तथा रॉड कॉन्सेशन ।

रॉड रियायतों के अनुसार चार्ल्स रॉड एवं थाम्पसन ने 100 पौंड प्रति माह, 1,000 मार्टीन हेनरी ब्रीच राइफल, 100,000 राउंड गोली तथा एक सैनिक स्टीमर जो कि जाम्बेसी नदी की रक्षा करे, लोबेंगुला को देने का निश्चय किया । इसके बदले लोबेंगुला ने माताबेला, मातोना

3- डी0 मार्टिन एंड फिलिप जॉनसन, उपर्युक्त, पृ0 36

लैंड तथा अन्य संबंधित भूभाग के खनिज एवं खनन का एकमात्र अधिकार रॉड एवं थाम्पसन को दिया ।[4]

इन रियायतों को सेसील रोड्स के ब्रिटानी दक्षिण अफ्रीका कंपनी को 10,00,000 पौंड में बेच दिया गया । सेसील रोड्स ने अंततः रॉड छूट को प्राप्त कर लिया जिसे वह बहुत पहले से चाहता था । साथ ही अन्य के लिए दरवाजा बंद कर दिया । यह रियायतें मूलतः एक खनिज अधिकार थी, कृषि के लिए जमीन की छूट लेने में मना लिया और यह जमीन छूट पुनः रोड्स कंपनी को बेच दी गयी । यद्यपि लोबेंगुला ने केवल खनिज संबंधी अधिकार कंपनी को दिया पर ब्रिटानी सरकार ने आज्ञा दी कि कंपनी एक सरकार की सारी जिम्मेदारी निभायेगी ।[5]

सभी संधियाँ अनपढ़ अफ्रीकी एवं बेईमान शिक्षित श्वेतों के बीच हुईं जो सिर्फ खनिज/संपदा के शोषण के उद्देश्य से की गयीं । अफ्रीकावासी बेईमान श्वेतों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य किये गये । यह भी यूरोपियनों का ही काम था कि वह समझाये कि संधि क्या है तथा इसकी शर्तें क्या हैं । धीरे धीरे यूरोपियों ने संपूर्ण रोडेशिया को हथिया लिया ।

ब्रिटानी सरकार की दक्षिण अफ्रीका कंपनी के प्रति स्वच्छंदता की नीति 1896-97 के आंदोलन के बाद बदल गयी । इस समय इंग्लैंड की नीति मुख्य उद्देश्य बढ़ते आंदोलन का दमन करना था । ब्रिटानी सरकार ने 1898 में एक संविधान प्रस्तावित किया । समझा गया कि यह कंपनी उपनिवेशी तथा मूल अफ्रीकी निवासियों के लिए न्यायसंगत होगी । इस समय जो विधान परिषद बनायी गयी थी उसमें कंपनी के पाँच मनोनीत सदस्य, चार निर्वाचित उपनिवेशी होते थे, कंपनी के

4- वही, पृ0 42

5- हॉवर्ड सीमॉन- रिसर्च रिपोर्ट नं0 55 : जिम्बाब्वे - ए कंट्री स्टडी स्कैंडेनेवियन इंस्टीट्यूट आफ अफ्रीकन स्टडीज, स्टाकहोम 1979, पृ0 14

प्रशासक अध्यक्ष के रूप में जिसे निर्णायक मताधिकार था तथा आवासी-आयुक्त जो ब्रितानी सरकार के प्रतिनिधि थे, मताधिकार नहीं था। गोरे उपनिवेशी को वहाँ के राजनीतिक मामले में कहने सुनने का अधिकार था पर अफ्रीकी जनता को कुछ भी अधिकार नहीं था। उस समय यह कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि काले अफ्रीकी श्वेत-वासी के साथ बैठकर राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श कर सकते हैं।[6]

सीसिल रोड्स की मृत्यु के बाद (1912) उपनिवेश का स्वायत्त-शासन की माँग बढ़ गयी। इस माँग को पूरा करने के लिए ब्रितानी सरकार या कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। 1907 में ब्रितानी सरकार ने कंपनी के मनोनीत सदस्यों को समाप्त कर उपनिवेशी के बहुमत को बढ़ा दिया। तेज होते आंदोलन एवं बढ़ते असंतोष के कारण ब्रितानी सरकार ने विधान परिषद में उपनिवेशियों की संख्या बढ़ा कर 15 कर दी। इससे पहले (1907में) उच्चायुक्त ने उपनिवेश में 1914 तक उत्तरदायी सरकार बनाने का वचन दिया था। पर समय आने पर यह कहकर वचन से हट गया कि उपनिवेशी आर्थिक रूप से उत्तरदायी सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं।[7]

प्रथम विश्वयुद्ध ने उत्तरदायी सरकार की माँग को पीछे ढकेल दिया पर युद्ध के शीघ्र बाद ब्रितानी सरकार की नीतियों ने उत्तरदायी सरकार की माँग को फिर से तेज कर तूल दिया। जब उत्तरदायी सरकार की माँग ने गति पकड़ ली तभी उपनिवेशी के हितों के शुभचिंतक उच्चायुक्त लार्ड बाक्सटन ने हरबर्ट स्टेनले को साम्राज्य सचिव नियुक्त किया जिसे एक संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा गया।

6- इत्माइल मलाम्बो- रोडेशिया - दी स्ट्रगल फार ए बर्थराइट, लंदन, 1972 पृ0 3

7- वही, पृ0 4

भाग्य ने श्वेतवासी का हमेशा साथ दिया । इसी समय उपनिवेशिक सचिव चर्चिल ने बॉक्सटन की अध्यक्षता में एक रॉयल आयोग की स्थापना की जिसका काम यह सुझाव देना था कि कब उत्तरदायी सरकार रोडेशिया को प्रदान की जाये ।

बॉक्सटन की अध्यक्षता में रॉयल आयोग ने अपने जो सुझाव प्रस्तावित किये वे कुल मिलाकर उपनिवेशी के ही पक्ष में थे । इस आयोग ने कहा कि उपनिवेशी को उत्तरदायी सरकार प्रदान कर दी जाये जो कि जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए । कुछ विषय जैसे - मूल निवासी एवं जमीन से संबंधित- ब्रितानी सरकार के ही अधीन रहें ।[8]

1922 में रोडेशिया के मतदाताओं से पूछा गया कि क्या वह दक्षिण अफ्रीका का पाँचवाँ प्रांत बनना चाहता है । इस पर रोडेशिया के श्वेत निवासियों ने (जनमत संग्रह द्वारा) इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया । तब से रोडेशिया ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया । तथापि संविधान ने बहुत हद तक रोडेशिया को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की और वह एक स्वायत्तशासी उपनिवेश के रूप में जाना जाने लगा । रोडेशिया की समस्याओं का समाधान एक डोमैनियन अधिकारी द्वारा किया जाता था न कि किसी उपनिवेशिक अधिकारी द्वारा । ब्रितानी सरकार ने अफ्रीकी जनता के विधायकी तथा मताधिकार संबंधी अधिकारों को अपने हाथ में रख लिया । किंतु कभी भी इस अधिकार का ब्रितानी सरकार ने प्रयोग नहीं किया । कालक्रम में इस विषय में एक संवैधानिक परंपरा विकसित हो गयी कि जब तक ब्रितानी सरकार द्वारा कोई विधेयक अनुमोदित नहीं होगा तब तक रोडेशिया की सरकार अफ्रीकी जनता से संबंधित कोई विधेयक स्वयं पास नहीं करेगा । इसी समय 1923 के संविधान के अनुसार

8- एलेन वैंडरीच - दी रोडेशियन प्राब्लम ए डाक्यूमेंटरी रिकार्ड, 1923-73, लंदन, 1975, पृ0 2

रोडेशिया ने पक्षपातपूर्ण एवं दमनकारी कानूनों को लागू किया और इस इच्छा ने उसकी डोमिनियन माँग को तीव्र कर दिया जो कि व्यावहारिक रूप से अल्पमत की सरकार शासन कर रही थी ।[9]

दक्षिणी एवं उत्तरी रोडेशिया को एक करने की योजना बहुत पुरानी थी । इसकी जड़ें कंपनी शासन तथा सेसिल रोड्स की साम्राज्यवादी नीतियों में ढूंढी जा सकती हैं जिसने मध्य अफ्रीका में एक "श्वेत प्रभुत्व" वाला ब्रितानी डोमिनियन स्थापित करने का बीज डाला । किंतु इस योजना को तब तक पुर्नजागृत नहीं किया गया जब तक कि वे उत्तरदायी सरकार की माँग को हासिल न कर लें । दक्षिणी एवं उत्तरी रोडेशिया को एक करने का दूसरा कारण यह था कि उत्तरी रोडेशिया में 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशाब्द में ताँबे की खोज हुई ।[10]

दक्षिण रोडेशिया के प्रधानमंत्री सर हुगीन्स ने दक्षिण रोडेशिया को उत्तरी रोडेशिया में मिला कर एक करने के विचार का काफी प्रचार किया । एकीकरण का यह विचार आर्थिक एवं राजनीतिक भावना से ओतप्रोत था । युद्ध के बाद दक्षिण रोडेशिया ने उत्तरी रोडेशिया के ताँबा, सीसा एवं जस्ता खानों की खोज के कारण, अपने उद्योगों को विकसित करना चाहा । साथ ही उसे एक बाजार की भी आवश्यकता थी जो कि उत्तरी रोडेशिया प्रदान कर रहा था ।[11]

दो दशाब्दी से अधिक ब्रितानी सरकार अंततः श्वेतवासी एकीकरण की माँग को नामंजूर करती रही । अंततः लगातार माँग के फलस्वरूप ब्रितानी सरकार ने 1937 में लार्ड ब्रोडीसला की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन की स्थापना की जिसका काम यह पता लगाना था कि दक्षिणी एवं उत्तरी रोडेशिया का एकीकरण संभव है या नहीं ।[12]

9- डारवर्ड सीमलॉग- रीसर्च रिपोर्ट नं0 53, पृ0 14

10-एलेन बी0 विंडरीच-दी रोडेशियन प्राब्लम ए डाक्यूमेंटरी रेकार्ड, 1923-73 (लंदन), 1975, पृ0 19

11-के0यंग : रोडेशिया एंड इंडीपेंडेंट-ए स्टडी इन ब्रिटिश कालोनियल पालिसी (लंदन) 1967, पृ0 38

12-एलेन बी0 विंडरीच, उपर्युक्त, पृ0 20

ब्लेडीसला आयोग के एकीकरण के विचार को नामंजूर कर दिया। आयोग ने कहा, "दो सरकारों के बीच संघवाद की मांग हमारे मत से सफल नहीं हो सकती क्यों कि दोनों सरकारों की दो प्रकार की जिम्मेदारियां हैं तथा सामाजिक एवं राजनीतिक विकास दो भिन्न स्तर पर है। दोनों के बीच एक बड़ी खाई है जो कि संघवाद की योजना को बाधा पहुंचाती है।[13]

ब्लेडीसला आयोग के सुझावों की चिंता किये बिना अल्पमत वाले यूरोपीयों ने एकीकरण की योजना को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पुनर्जागृत किया। तब इंगलैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी जो कि अफ्रीकी विदेश एवं अपनी ही पार्टी के विरोधी सदस्यों के भय से, इस विषय पर रोडेशियाई श्वेतवासियों से समझौता करने के लिए तैयार न थी।

तथापि 1950 में लेबर पार्टी संघीय शासन के विषय पर नये सिरे से विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने पर सहमत हो गयी। किंतु इसके साथ ही कई शर्तें भी लगा दी गयीं थी : 1- सम्मेलन का एकमात्र काम अन्वेषण संबंधी होगा, 2- भाग लेने वाली सरकार कोई वचनबद्ध नहीं होगी और 3- किसी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व अफ्रीकी जनता के मतों का पूरा ख्याल रखा जायेगा। यह तीसरी शर्त समझौते के मार्ग में बड़ी बाधा बन गयी। फलतः संघीय शासन के लिए सम्मेलन के सुझावों का पालन न हो सका।[14]

मध्य अफ्रीका में संघ शासन के लिए जो परामर्श श्वेत रोडेशियन एवं ब्रितानी सरकार के बीच चल रहा था वह इंगलैंड में 1951 के चुनाव के कारण रुक गया। जब कंजर्वेटिव सरकार इंगलैंड में आयी तब नये

13-एलेन बी० विंडरीच, उपर्युक्त, पृ० 20

14-वही, पृ० 23

उपनिवेशिक सचिव ओलीवर लीटलेटन ने घोषणा की कि एक सम्मेलन बुलाया जायेगा जिसमें संघीय योजना पर विचार विमर्श किया जायेगा जो कि मध्य अफ्रीका के एकीकरण का आधार होगा ।

जब इंगलैंड में जनवरी 1953 में संघीय शासन पर सम्मेलन हुआ तो यह कहा गया कि - "अगर मध्य अफ्रीका के तीनों देशों की संपदा के विकास और विश्व में अपनी समुचित महत्ता के लिए एक नजदीकी राजनीतिक संघ आवश्यक है । व्यक्तिगत रूप से भूभाग छेद्य व भेद्य है... तीनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की सहायक है । यदि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास चाहते हैं तो तीनों में नजदीक का संबंध होना अति आवश्यक है ।"[15]

1953 में ब्रितानी सरकार ने द0 रोडेशिया के साथ उत्तरी रोडेशिया तथा न्यासालैंड के भूभाग को मिला कर एक संघीय शासन की स्थापना की । साथ ही यह भी कहा गया कि इसके विकास एवं स्थिति पर सात से नौ वर्षों के बीच एक पुनर्विलोकन किया जायेगा । वेलेंस्की के अधीन संघीय सरकार एक डोमेनियन सरकार के लिए चिंतित थी । तथा ब्रितानी सरकार राजी हो गयी कि 1960 में पुनरावलोकन किया जायेगा । इसके अलावा ब्रितानी सरकार पर अफ्रीकी राष्ट्रवादी, जो कि संघीय शासन के विरोध में था, का भी प्रभाव आ रहा था ।

इस परिस्थिति में लार्ड मांकटन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गयी जिसका काम वर्तमान रवैये को देखना, संघ शासन की संभावना पर विचार करना तथा पुनरावलोकन सम्मेलन के लिए तैयारी करना था । न्यासालैंड में उपद्रव के कारण एक जाँच आयोग की स्थापना की गयी जिसने संघीय शासन के समाप्त करने के पक्ष में सुझाव दिया ।

15- एलेन बी0 विंडरीच, उपर्युक्त, पृ0 27

मॉन्कटन आयोग भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि "वर्तमान संघीय शासन को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता । दक्षिण अफ्रीका की पक्षपातपूर्ण एवं रंगभेद नीति के कारण अफ्रीकावासियों में संघीय शासन के प्रति घृणा है ।[16]

मॉन्कटन आयोग की रिपोर्ट के बाद दक्षिणी रोडेशिया सरकार के सामने दो ही विकल्प थे -- या तो वह अपनी रंगभेद की नीति को बदले या फिर संघीय शासन को समाप्त कर दे । दक्षिण रोडेशिया की सरकार संघीय शासन को समाप्त करने के लिए ही राजी हुई और अंततः 1963 में संघीय शासन समाप्त हो गया । दक्षिणी रोडेशिया ने अपनी रंगभेद की नीति को बरकरार रखा ।[17]

संघ शासन भंग होने का मुख्य कारण दक्षिण रोडेशिया एवं उत्तरी रोडेशिया में बढ़ता अफ्रीकी राष्ट्रवाद था । उत्तरी रोडेशिया जाँबिया के रूप में तथा न्यासालैंड मलावी के रूप में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्य हो गये । तथा दक्षिणी रोडेशिया स्वायत्तशासी उपनिवेश रह गया जो कि अल्पसंख्यक श्वेतवासियों द्वारा शासित था ।

1961 में ब्रितानी संसद द्वारा एक नये संविधान का अनुमोदन किया गया जिसमें ब्रिटेन ने अधिकारों की घोषणा एवं बहुजातीय संवैधानिक परिषद के बदले निषेधाधिकार अपने हाथों में रख लिया । एक नये मताधिकार का निर्माण किया गया जो कि धन सम्पत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता पर आधारित था ।

श्वेत अल्पमत सरकार इस बात से परिचित थी कि वीटो अधिकार इंगलैंड के पास है जिसके द्वारा किसी भी समय वह हस्तक्षेप कर सकता है । अतः रोडेशिया की सरकार ने स्वतंत्र सरकार की माँग शुरू कर दी ।

16- एलेन विंडरीच - वही, पृ० 32

17- वही, पृ० 33

ब्रिटेन ने इस बात से इनकार कर दिया कि बहुमत शासन के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। कई बार समझौता बिना किसी अनुबंध के समाप्त हो गया।

रोडेशिया की स्वतंत्रता का प्रश्न ब्रितानी सरकार के लिए 1953 में मैकमिलन से लेकर 1964 में विल्सन तथा 1970 में हीथ तक लगातार एक मुख्य मुद्दा बना रहा। ब्रितानी सरकार निरंतर यह तर्क प्रस्तुत करती रही कि अन्य राज्यों की तरह रोडेशिया में भी शासन बहुमत के आधार पर हो तभी उसे स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। किंतु रोडेशिया की अल्पमत सरकार ने बहुमत शासन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और यह दावा किया कि रोडेशिया 1923 से ही स्वायत्त शासन है जो कि स्वतंत्र सरकार के सभी गुणों से युक्त है।[18]

1961 के संवैधानिक सम्मेलन को छोड़कर किसी भी सम्मेलन में अफ्रीकी राष्ट्रवादियों को शामिल नहीं किया गया था-- चाहे वह स्वतंत्रता का सम्मेलन हो या राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारों का सम्मेलन हो। 1961 के सम्मेलन में अफ्रीकियों को सम्मिलित करने का मुख्य कारण तत्कालीन जटिल समस्या का समाधान करना ही था।

जब 1963 में विक्टोरिया प्रपात में संघीय शासन को समाप्त करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया तब दक्षिण रोडेशिया की सरकार रोडेशिया फ्रंट के प्रधानमंत्री फील्ड ने स्वतंत्रता की मांग को और भी बढ़ा दिया।

प्रतिरक्षा के मामले पर विरोध होने के बाद इस सम्मेलन में किसी भी बात पर विरोध नहीं हुआ। संघ शासन को समाप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हुई तथा ब्रितानी संसद की सहमति से 1963 में संघ शासन भंग/संघीय विधेयक पारित हो गया।[19]

18- स्लेन विंडरीच - वही, पृ0 11

20- वही, पृ0 17

रोडेशियाई मोर्चे के प्रधानमंत्री फील्ड ने 1961 के संविधान के आधार पर रोडेशिया की स्वतंत्रता की मांग को ब्रितानी सरकार की नामंजूरी के बाद भी नहीं छोड़ा । फील्ड स्वतंत्रता के लिए ब्रितानी सरकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था । स्वतंत्रता के लिए दो साल तक परामर्श बिना किसी सफलता के चालू रहा । इसमें भाग लेने वाले बदलते रहे । यहाँ तक कि ब्रिटेन में मैकमीलन के स्थान पर सर एलिक डगलस ह्यूम तथा रोडेशिया में फील्ड के स्थान पर स्मिथ आ गये ।[20]

इआन स्मिथ का शासन में आना रोडेशियाई मोर्चे की मनःस्थिति में एक परिवर्तन का संकेत था जो कि इआन स्मिथ की जनता के सामने उद्घोषणा से ही स्पष्ट हो गया था । फिल्ड के स्थान पर स्मिथ का शासन में आना रोडेशिया की राजनीति में उतना परिवर्तन का संकेत नहीं था जितना कि गारफील्ड टॉड के स्थान पर वाइटहेड का आना तथा वाइटहेड के स्थान पर फील्ड का आना था । पहले के प्रधानमंत्रियों को इस कारण हटाया गया था कि वे सब पक्षपातपूर्ण कानून में सुधार करना चाहते थे । जैसे टॉड ने मताधिकार में परिवर्तन चाहा, वाइटहेड ने जमीन विभाजन करना चाहा । इस तरह की बात फील्ड के साथ नहीं थी । रोडेशिया के दोनों नेता (फील्ड और स्मिथ) के बीच रणनीति एवं तरीके को लेकर विभेद था ।[21]

रोडेशिया का नेतृत्व संभालने के पहले ही स्मिथ स्वतंत्रता के (बाद के) परिणामों के बारे में बातें करने लगे । जनवरी 1964 में स्मिथ ने दक्षिणपंथी पत्रिका "न्यूज फ्रंट" से कहा कि एक बार जब रोडेशिया स्वतंत्रता हासिल कर लेता है तब किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा । जहाँ तक लंदन का

20- एलेन विंडरीच, उपर्युक्त, पृ0 17-18

21- वही, पृ0 19

संबंध है, स्मिथ का सोच था कि यह मात्र कुछ वर्षों की समस्या होगी।[22]

रोडेशियन फ्रंट के सदस्यों का अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए इआन स्मिथ अपने पूर्वाधिकारी से भी अधिक स्वतंत्रता की माँग करने लगा। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्मिथ ने समझौते की तरीका अपनाया। स्मिथ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिना निर्वाचक के समर्थन का वह एकपक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करेगा।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रोडेशिया फ्रंट की मुख्य नीति थी कि किसी भी प्रकार का आंतरिक विरोध न हो -- चाहे वह अफ्रीकी हो या यूरोपीय। अफ्रीकी विरोध की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी क्यों कि अन्य भूभागों के विपरीत रोडेशिया के राष्ट्रवादी नेता अपने अंतिम उद्देश्य-- बहुमत शासन-- पर एक मत नहीं थे। श्वेत अल्पमत सरकार के विरुद्ध अपने शक्ति को मजबूत करने के स्थान पर अफ्रीकी नेता छोटी-छोटी बातों पर लड़ रहे थे कि कौन आंदोलन का नेतृत्व करता है। जब रोडेशियन फ्रंट दिसंबर 1962 में शासन में आया तब से अफ्रीकी राष्ट्रीय आंदोलन श्वेत सरकार की दमनकारी नीति के कारण और भी कमजोर हो गया। इसके साथ ही बढ़ती हुई दमनकारी नीति में किस प्रकार का युद्धकौशल अपनाया जाय तथा इस नाजुक समय में कौन नेतृत्व करे, राष्ट्रवाद आंदोलन/ही कमजोर साबित कर रहा था।[23]

अफ्रीकी विरोध को कुचलने के बाद रोडेशिया फ्रंट ने यूरोपीय विरोध का सामना करना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ती हुई लोकप्रियता एवं ब्रितानी सरकार को मनाने के लिए अटल, जनता से स्वतंत्रता के लिए आदेश ले चुके रोडेशिया फ्रंट ने अपनी योजना का अनुपालन किया। रोडेशिया फ्रंट ने अफ्रीकी तथा यूरोपीयनों का समर्थन जीतने की कोशिश की।

22- एलेनविंडरिच, उपर्युक्त, पृ0 19

23- वही, पृ0 23

इंग्लैंड में 1964 के आम चुनाव में लेबर पार्टी के शासन में आने से रोडेशिया का संकट और भी गहरा हो गया। लेबर पार्टी रोडेशिया में संघीय शासन का शुरू से विरोध इस बात पर करती आ रही थी कि यूरोपीय अल्पसंख्यक का आधिपत्य होगा। फिर भी संघ शासन के लादे जाने के विरोध के उद्देश्य में असफल होने के बावजूद लेबर पार्टी ने अफ्रीकी वासी को राजनीति में हिस्सेदारी पर जोर दिया।

रोडेशिया का नेतृत्व लेने के बाद इआन स्मिथ ने अपने प्रथम अभिभाषण में कहा कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो रोडेशिया की जनता को अपना भाग्य निर्धारित करने के लिए दक्षिणी रोडेशिया के संविधान को संशोधित किया जायेगा। किंतु लेबर पार्टी रोडेशिया की अल्पमत सरकार को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी। लेबर पार्टी ने यही रुख अपनाया जब तक कोन्जर्वेटिव पार्टी ने रोडेशियन फ्रंट के साथ वार्ता की। लेबर पार्टी ने "नीबमार" [नो इंडिपेंडेंट बिफोर मैजोरिटी रूल या बहुमत शासन से पहले स्वतंत्रता] सिद्धांत का प्रतिपादन किया जब रोडेशिया स्वतंत्रता का प्रश्न पार्टी के सामने आया।[24]

यद्यपि लेबर पार्टी ने बुरे परिणामों की चेतावनी तो दी पर यह स्पष्ट हो गया कि वह रोडेशिया के ऊपर किसी प्रकार का संवैधानिक निपटारे का दबाव नहीं डालेगा। लेबर पार्टी ने मुख्य रूप से सहमति और सहयोग का सहारा लिया। उसने शक्ति के स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का स्थानांतरण किया और अल्पमत से बहुमत पर निर्भर रहा जब कि वह विपक्ष में था तब इसका विरोध कर रहा था।

24- एलेन विंडरीच - ब्रिटेन एंड दी पालिटिक्स आफ दी रोडेशियन इंडीपेंडेंट, पृ0 3।

लेबर पार्टी और रोडेशियन फ्रंट के बीच संधिवार्ता बिना कुछ निष्कर्ष के ही खत्म हो गयी । संधिवार्ता का भंग होना कोई आश्चर्यजनक बात न थी क्योंकि मेरो सरकार द्वारा जो संधि की शर्तें रखी गयी थीं वे वही थी जो पूर्व दो ब्रितानी प्रधानमंत्रियों के साथ रखी गयी थी ।

लेबर पार्टी ने पाँच सिद्धांतों का प्रतिपादन किया । लेकिन ऐसा समझा जाता था कि इसके अर आगे बातचीत की जायेगी ।

1- बहुमत शासन का सिद्धांत तथा बिना बाधा के इसके विकास की इच्छा, जो 1961 के संविधान में अंकित है, को बरकरार रखा जाना ।

2- संविधान के प्रतिगामी संशोधन के विरुद्ध सुरक्षा दी जाये ।

3- अफ्रीकी जनसंख्या की राजनीतिक स्थिति में तुरंत सुधार किया जाये ।

4- जातीय रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये ।

5- ब्रितानी सरकार को संतुष्ट होना होगा कि स्वतंत्रता के लिए कोई प्रस्तावित आधार रोडेशिया की जनता को मान्य होगा ।[25]

लेबर पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा चेतावनी देने के बाद कुछ ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री विल्सन से रोडेशिया के नेताओं ने लंदन में बातचीत शुरू कर दी । चार दिन की वार्ता के बाद कोई भी हल नहीं निकल सका ।

पुनः बातचीत जब सैलिसबरी में शुरू हुई तब अंतिम दिन तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकल सका । साथ ही केवल बातचीत भंग होना ही निश्चित नहीं हुआ बल्कि यह भी निश्चित हो गया कि अवैध घोषणा भी निश्चित है । प्रधानमंत्री विल्सन ने रोडेशिया के मंत्रिमंडल के सामने दो प्रस्ताव रखे -- प्रथम, जनमत संग्रह का था जिसमें स्मिथ के बहुमत के दावे की जाँच करनाथा कि रोडेशिया के सभी जनता 1961 के

25- एलेन विंडरीच - द रोडेशियन प्राब्लम, पृ0 205-6

संविधान के आधार पर स्वतंत्रता चाहती है । किंतु यह जनमत संग्रह नवंबर 1964 के जनमत संग्रह से भिन्न था जिसमें अफ्रीकी जनता को मत देने का अधिकार था तथा राजनीतिक संगठनों को स्वतंत्रता एवं विचार-विमर्श करने का अधिकार था । दूसरा-- रोडेशिया के मुख्य न्यायाधीश सर बीडल के नेतृत्व में एक रॉयल आयोग की स्थापना करना था जो 1961 के संविधान में संशोधन के लिए सुझाव देता ।[26]

जब कि प्रधानमंत्री विल्सन ने रॉयल आयोग को समस्या समाधान के लिए एक और प्रयास माना पर इआन स्मिथ ने भविष्यवाणी की कि अगर यह प्रयास असफल हो जायेगा तो समझौते के लिए किया गया अंतिम प्रयास समाप्त ही माना जायेगा । वस्तुतः स्मिथ की सरकार ने विल्सन के सभी विकल्प नामंजूर कर दिये । यहाँ तक कि रॉयल आयोग को किसी भी प्रकार के संवैधानिक सुझाव देने से मना कर दिया । साथ ही स्मिथ ने जनमत संग्रह को प्रस्तावित संविधानों से अलग माना । अब रोडेशियन फ्रंट ने रोडेशिया में 5 नवंबर 1965 को आपातस्थिति घोषित कर दी जो कि रॉयल आयोग को अपना काम करने से रोकना था ।[27] और अंततोगत्वा 11 नवंबर 1965 को इआन स्मिथ ने अपनी एकपक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी ।

26- एलन विंडरीच, वही, पृ0 51

27- वही, पृ0 54

अध्याय : 2

रोडेशिया के घटनाक्रम में अपपीड़न का प्रयोग

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपपीड़न का प्रयोग किया जाता है । अपपीड़न एक सरल एवं आम तरीका है जिसके द्वारा उद्देश्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है । अपपीड़न का प्रयोग या तो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है । पर सामूहिक रूप से अपपीड़न का प्रयोग बहुत प्रभावकारी होता है । रोडेशिया के घटनाक्रम में अपपीड़न का प्रयोग सैनिक या शक्ति के रूप में नहीं किया गया फिर भी इस प्रकार के अपपीड़न की माँग काफी थी । यहाँ पर आर्थिक अपपीड़न का सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया गया जो कि अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर आर्थिक अपपीड़न का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है ।

"एकपक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा" के बाद रोडेशिया विश्व राजनीति के सामने उभर कर आ गया । विश्व की नजरें एकाएक जोरों से खिंच गयी । अब रोडेशिया का प्रश्न मात्र ब्रितानी सरकार रोडेशिया फ्रंट और अफ्रीकी राष्ट्रवादियों की ही चिंता का विषय नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व के सामने एक मुख्य समस्या बनकर खड़ा हो गया ।

कुछ अनुशक्ति

लेबर सरकार ने रोडेशिया में हस्तक्षेप करने के बजाय बहुत सारे ऐसे उपायों का अनुमोदन किया जो कि स्वभाव से दंडात्मक नहीं थे । शुरू में विशिष्ट आर्थिक प्रतिबंध लादे गये पर तेल या उससे उत्पादित वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया जो कि रोडेशिया को निराश करने के लिए आवश्यक था । रोडेशिया की मुद्रा स्थिरता को नष्ट करने के

TH-1661
V,623;1956'N8 Disser
152M4

किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की गयी थी जो कि एक महत्वपूर्ण विलोपन था ।[28] ब्रिटेन द्वारा लिये निम्न प्रतिबंध लगाये गये :

1- अस्त्र-शस्त्र का निर्यात बंद किया जायेगा ।
2- सभी ब्रितानी सहायता बंद कर दी जायेगी ।
3- रोडेशिया को स्टर्लिंग से हटाया जा रहा है ।
4- विशेष विनिमय नियंत्रण को लागू किया जायेगा ।
5- ब्रितानी पूँजी का निर्यात रोडेशिया में नहीं किया जायेगा ।
6- लंदन पूँजी बाजार में अब रोडेशिया को अनुमति नहीं दी जायेगी ।
7- 1932 की ओटावा संधि, जिसके द्वारा रोडेशिया के साथ व्यापार किया जाता है, को रद्द किया जा रहा है ।
8- राष्ट्रमंडल वरीयता का अभियान क्षेत्र से रोडेशिया को निलंबित किया जाता है तथा रोडेशिया की वस्तु इंगलैंड में जाने पर अभियान वरीयता को प्राप्त नहीं करेगा ।
9- रोडेशिया के तंबाकू की खरीदारी पर रोक लगायी जायेगी ।
10- इंगलैंड राष्ट्रमंडल के देशों से आग्रह करता है कि रोडेशिया के साथ चीनी के समझौते को मुअत्तल कर दे तथा आगे की खरीदारी को बंद कर दे ।[29]

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी "एकपक्षीय घोषणा" को गलत बताया तथा ब्रितानी सरकार से अनुरोध किया कि वह गैरकानूनी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करे । 18नवंबर, 1965 को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई जिसमें

28- एलन विंडरीच - ब्रिटेन एंड दी पालिटिक्स आफ रोडेशियन इंडीपेंडेंट (लंदन), 1978, पृ0 64

29- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन नवंबर 1-30, 1965, प्रकाशित अफ्रीका रिसर्च लिमिटेड, 97 पार्लियामेंट स्ट्रीट सिटी आफ इक्सेटर, इंगलैंड, पृ0 406-ए

यह प्रस्ताव पारित किया गया कि :

1- एकपक्षीय घोषणा के परिणाम स्वरूप समस्या गंभीर हो गयी है एवं ब्रितानी सरकार को उसे समाप्त करना चाहिए ।

2- सुरक्षा परिषद आमसभा के प्रस्तावना 1514 (XV) का समर्थन करता है ।

3- अल्पमत गोरी सरकार द्वारा अनधिकृत सत्ताग्रहण का खंडन किया जाता है तथा एकपक्षीय घोषणा का कोई कानूनी महत्व नहीं है ।

4- ब्रितानी सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वह विद्रोही सरकार को समाप्त करे ।

5- सुरक्षा परिषद ब्रितानी सरकार से पुनः अनुरोध करती है कि वह अल्पमत की अनाधिकृत शक्ति को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाये ।

6- सुरक्षा परिषद अनुरोध करती है कि कोई भी देश अल्पमत सरकार को मान्यता न दे या किसी भी प्रकार का राजनीतिक संबंध स्थापित न करे ।

7- 1961 के संविधान का कार्यसंचालन नहीं हो सका है अतः ब्रितानी सरकार को ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिससे कि अफ्रीकी जनता को आत्मनिर्णय करने का अधिकार हो ।

8- सुरक्षा परिषद सभी देशों से अनुरोध करता है कि किसी भी प्रकार के कार्य को न करे जो अवैध सरकार को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता हो विशेष रूप से सैनिक एवं अस्त्र शस्त्र की सहायता न करे तथा रोडेशिया से सभी प्रकार के आर्थिक संबंध तोड़ ले तथा पेट्रोल तथा उससे उत्पादित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दे ।

9- सुरक्षा परिषद ब्रितानी सरकार से अनुरोध करती है कि उसने जो कार्रवाई की घोषणा की है उसका प्रभावकारी ढंग से पालन करे ।

10- सुरक्षा परिषद अफ्रीकी एकता संगठन से अनुरोध करता है कि वह राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों का पालन करने में सहायता करे ।

11- सुरक्षा परिषद निश्चित करती है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होगी समस्या का हमेशा पुनर्विलोकन किया जायगा ।[30]

शीघ्र ही ब्रितानी सरकार ने रोडेशिया के निर्यात पर 95 प्रतिशत तक प्रतिबंध लगा दिया । ब्रितानी नागरिकों द्वारा रोडेशिया में मुद्रा भुगतान या भेजी गयी मुद्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया । अंततः ब्रितानी सरकार ने "आर्डर-इन-कौंसिल" 17 दिसंबर 1965 के द्वारा तेल एवं तेल से उत्पादित वस्तुओं के रोडेशिया को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ।[31]

ब्रितानी सरकार द्वारा रोडेशिया के घटनाक्रम में जो कदम उठाये गये उससे राष्ट्रमंडल देशों के नेतागण असंतुष्ट थे । इसलिए उन्होंने केवल रोडेशिया की समस्या पर विचार विमर्श के लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाने पर प्रस्ताव रखा । नाईजीरिया की राजधानी लागोस में 11 जनवरी 1966 को नाईजीरिया के ही प्रधानमंत्री तर अबुबाकर ताफेवा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई ।

बढ़ते दबाव के प्रति विल्सन का उत्तर संतोषजनक नहीं था । राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के संयुक्त निर्णय, (जिसमें विद्रोही सरकार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया था), को विल्सन मानने के लिए बाध्य था तथा दूसरी ओर इंगलैंड तथा रोडेशिया से भी विल्सन पर दबाव बढ़ रहा था कि वह मेल-मिलाप व सामंजस्य का रुख अपनाये । इन विरोधाभास की परिस्थितियों का सामना करने के लिए विल्सन ने संधिवार्ता की योजना को पुनः शुरू किया साथ ही कुछ और आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा दिये ।[32]

पर वास्तविक आर्थिक प्रतिबंध अभी भी बाकी थे-- क्योंकि दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल के आर्थिक संबंध अभी भी रोडेशिया के साथ

30- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन, उपर्युक्त, पृ0 412 ए बी सी

31- एलन विंडरीच-ब्रिटेन एंड दी पार्लिटिक्स आफ रोडेशियन इंडीपेंडेंट, (लंदन), 1978, पृ0 69-70

32- वही, पृ0 78

बरकरार थे । रोडेशिया में तेल इन्हीं दो स्रोतों से आता था तथा रोडेशिया द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात भी इसी के साथ होता था । जब तक दक्षिण अफ्रीका एवं पुर्तगाल की सरकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता तब तक वास्तविक रूप में आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और इस काम को करने के लिए लेबर सरकार का कोई इरादा भी नहीं था । साथ ही लेबर सरकार रेडियो टेलीफोन, डाक, समुद्री तार के द्वारा रोडेशिया से जो संबंध था उसे तोड़ना नहीं चाहता था जब कि इस विषय पर राष्ट्रमंडल के देशों तथा राष्ट्रसंघ में विचार विमर्श हो रहा था ।[33]

लेबर सरकार बखूबी जानती थी कि जब तक तेल पर ठीक तरहसे रोक नहीं लगायी जायेगी तब तक आर्थिक प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं है । जलमार्ग के पहरे के लिए प्रहरी जलपोत को हिंद महासागर में भेजा गया पर यह कार्य निरर्थक था क्योंकि इस जलपोत को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था कि वह दूसरे जलपोत का अन्वेषण खोज कर सके या अवरुद्ध कर सके ।[34]

27 अप्रैल 1966 को विल्सन ने कहा कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाये ताकि बातचीत की जा सके । यह वार्ता जो "बातचीत के बारे में बातचीत" से जाना जाता है, लंदन के बाहटहाल में 9 मई, 1966 को शुरू हुई । ।बाद में जून तथा अगस्त में सेल्सिबरी में वार्ता जारी रही। यह बैठक बहुत ही गोपनीय थी पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका । न ही कोई संयुक्त घोषणा की गयी । इस "बातचीत के बारे में बातचीत" का सर्वत्र विरोध हुआ । राष्ट्रसंघ,

---

33- एलन विंडरीच, उपर्युक्त, पृ0 79
34- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन 1-30 अफ्रीका रिसर्च लि0, 1966, पृ0 517 ए, 558 ए, 1219 बी,सी

राष्ट्रसंघ, राष्ट्रमंडल एवं जांबिया सरकार ने विशेष रूप से विरोध किया ।[35]

अफ्रीकी एकता का संगठन (ओ०ए०यू०) की मुक्ति समिति का 9वां अधिवेशन दारेसलाम में 29 जून से 1 जुलाई तक हुआ जिसमें इंगलैंड - सेलिसबरी वार्ता की आलोचना की गयी तथा अपनी विज्ञप्ति में इंगलैंड से आग्रह किया कि वह सैनिक शक्ति का प्रयोग कर रोडेशिया में बहुमत की सरकार स्थापित करे ।[36] राष्ट्रसंघ अपनी सामान्य सभा में दो प्रस्ताव 86-2 तथा 89-2 के बहुमत से, जिसमें ब्रिटेन अनुपस्थित था, पास किये गये । दोनों प्रस्तावों में "बातचीत के बारे में बातचीत" की कड़ी आलोचना की गयी तथा कहा गया कि इससे अफ्रीकी जनता का स्वाधीनता के असंक्रामणीय अधिकार संकट में पड़ सकते हैं तथा ब्रितानी सरकार को याद दिलाया कि अवैध सरकार से किसी प्रकार की वार्ता उचित नहीं ।[37]

"एकपक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा" को रद्द करने में असफल रहने के बाद ब्रितानी सरकार ने एक संधिवार्ता के लिए एक लंबी श्रृंखला शुरू की जो अप्रैल 1966 से शुरू हुई और अंतर्विराम के बाद तब तक चालू रही जब तक कि कंजरवेटिव पार्टी की सरकार (सर एलिक डग्लस होम के नेतृत्व में) सत्तारूढ़ रही ।

अवैध सरकार द्वारा अफ्रीकियों पर कस कर दमन एवं अत्याचार बढ़ता गया । अल्पमत सरकार की निंदक करतूतों की सभी ओर से आलोचना हुई । राष्ट्रमंडल एवं राष्ट्रसंघ ने जम कर आलोचना की । ब्रितानी सरकार पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह रोडेशिया के विरुद्ध कुछ ठोस कार्रवाई करे।

35- ब्रान विंडरीच, उपर्युक्त, पृ० 88

36- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन, जून 1-30, 1966, पृ० 547 ए

37- एलन विंडरीच, उपर्युक्त, पृ० 97-98

सैनिक शक्ति की कार्रवाई बहुत पहले से ही नामंजूर कर दी गयी थी। अतः अब आर्थिक प्रतिबंध ही एकमात्र तरीका रह गया था जिसके द्वारा रोडेशिया को बाध्य किया जा सकता था। राष्ट्रसंघ में इंग्लैंड के स्थाई प्रतिनिधि ने रोडेशिया के विरुद्ध व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। यह काम आसान नहीं था क्योंकि लार्ड काराडाम को यह विश्वास दिलाना था कि इंग्लैंड सुरक्षा परिषद की ऐसी कार्रवाई के आह्वान को ब्रिटेन स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सैनिक शक्ति के उपयोग तथा दक्षिण अफ्रीका से सीधे मुकाबले की बात हो।

29 मई, 1968 कोररोडेशियन घटना पर सुरक्षा परिषद के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें इंग्लैंड एवं अफ्रीकी एवं एशियाई देश एक साथ थे।[38]

बदलते हुए परिवेश में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विल्सन ने रोडेशिया की समस्या के समाधान के लिए एच0 एम0 एस0 फीयरलेस जलपोत पर जिब्राल्टर में 1968 में 9 से 13 अक्तूबर तक बातचीत की। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े रहे। 13 अक्तूबर को संयुक्त घोषणा में बातचीत समाप्त कर दी गयी पर यह भी कहा गया कि संधिवार्ता का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है पर भविष्य में समझौता किया जा सकता है।[39]

फीयरलेस वार्ता का विरोध काफी हुआ। अफ्रीकी नेता साइथाल ने यहाँ तक कहा कि यह अव्यावहारिक है तथा यह ब्रितानी सरकार की ओर से केवल ढोंग व दंभ है।[40] जनवरी 7-15, 1969 तक लंदन में राष्ट्रमंडल देशों के प्रधान की बैठक में फीयरलेस प्रस्ताव का

38- एलन विंडरीप, उपर्युक्त, पृ0 127
39- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन, 1-30 अक्तूबर, 1968, पृ0 1216सी-17ए
40- विस्तृत विवरण अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन, 1-30 नवंबर, 1968, पृ0 1272-73

स्वागत नहीं किया गया तथा इसे अमान्य करार दिया गया । संयुक्त घोषणा में फियरलेस प्रस्तावना को वापस ले लेने को कहा गया ।[41]

फीयरलेस संधिवार्ता भंग होने के बाद रोडेशियन सरकार ने अपना गणतांत्रिक संविधान लागू करने तथा यूरोपीयन निर्वाचक गण से संविधान एवं गणतंत्र पर जनमत संग्रह करने के लिए आगे कदम बढ़ाया । संविधान का सारांश ब्रितानी प्रस्तावित पाँच सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा था तथा गणतंत्र घोषित कर किसी भी प्रकार का औपचारिक संबंध इंगलैंड के साथ भंग कर रहा था । अतः समझौते की संभावना और भी क्षीण हो गयी ।

"एकपक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा" के चार वर्षों के बाद रोडेशियन फ्रंट की सरकार ने गणतांत्रिक संविधान कार्यान्वित किया जिसके लिए काफी दिनों से आइन स्मिथ वचनबद्ध था । यद्यपि अल्पमत की सरकार ने 1965 में नया संविधान लागू किया पर वह वास्तविक रूप से 1961 का ही संविधान था । 1961 के संविधान में कुछ परिवर्तन लाये गये जैसे संविधान संशोधन के कठिन तरीकों को समाप्त कर दिया गया जिसमें कि जनमत संग्रह के द्वारा सभी जातियों के लोगों से सहमति ली जाती थी। साथ ही लंदन के प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया ।[42]

जब अनुदार दल (कंजरवेटिव पार्टी) इंगलैंड की राजनीतिक सत्ता में आयी तो 1971 में उसने अल्पमत की सरकार के साथ संधिवार्ता शुरू की । अनुदार सरकार को आर्थिक प्रतिबंध से उत्पन्न नयी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था । टोरी पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी आदेशात्मक प्रतिबंध को अस्वीकार किया था हालाँकि इस विषय पर मतदान विभाजित था । जब सत्ता में आया तब अनुदार दल ने इसे

41- राउंड टेबल, अक्टूबर 1969, नं0 234, पृ0 217-19

42- एलन विंडरीच, रोडेशियन प्राब्लम (लंदन) 1975, पृ0 71

अंतरराष्ट्रीय प्रयास के रूप में स्वीकार किया तथा एक दबाव डालने का माध्यम माना जिसके द्वारा रोडेशिया सरकार को संधिवार्ता में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है । इंग्लैंड के नये प्रधानमंत्री सर एलिक डगलस ह्यूम ने 1969 के संविधान के बातचीत के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया फिर भी इस संविधान को पहले के संविधान की अपेक्षा संधिवार्ता में बड़ी रूकावट माना ।

जब जनवरी 1971 में राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन सिंगापुर में हुआ तब अनुदार दल की सरकार को रोडेशिया से बातचीत करने पर कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा । दक्षिण अफ्रीका को अस्त्र-शस्त्र बेचने, जो कि इसके पूर्वाधिकारी द्वारा राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना के अनुसार बंद कर दिया था, के कारण आलोचना सहनी पड़ी थी । अनुदार दल की सरकार के शस्त्र बेचने के निर्णय की आलोचना अफ्रीकी एकता संगठन की । सितंबर 1970 की बैठक में अदीस अबाबा में तथा गुटनिरपेक्ष देशों के लुसाका सम्मेलन में भी की गयी ।[43]

सिंगापुर में राष्ट्रमंडल देशों की आलोचना को बाधा न मानते हुए सर एलिक डगलस ह्यूम ने रोडेशियन फ्रंट से बातचीत शुरू की किंतु इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि समझौते के लिए कोई प्रस्तावना रोडेशिया की सभी जनता को मान्य होना चाहिए । ब्रितानी सरकार ने रोडेशियन फ्रंट के नेता के साथ शिखर वार्ता के लिए एक साल तक पृष्ठभूमि तैयार की। मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री स्मिथ भी संधिवार्ता के लिए संकेत देने लगे । स्मिथ ने सेलिसबरी में "डेली टेलीग्राफ" के संवाददाता से कहा कि ब्रिटेन के साथ समझौते की संभावना बढ़ गयी है क्यों कि अनुदार दल को रोडेशिया की समस्या और उसकी सफलताओं का अच्छा ज्ञान है ।[44]

43- एलन विंडरीच, उपर्युक्त, पृ0 166

44- वही, पृ0 168

इस वार्ता शृंखला के बाद जो भी समझौता रोडेशिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। उसका चारों ओर से विरोध हुआ विशेष रूप से अफ्रीकी देशों राष्ट्रमंडल तथा राष्ट्रसंघ की ओर से। निर्वासित जानु और जापु[45] के प्रवक्ता ने लुसाका में कहा कि यह समझौता अफ्रीकी जनता के साथ पूर्ण विश्वासघात है। इस समझौते से किसी प्रकार की आशा भी नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रपति कौंडा एवं न्येरेरे ने ब्रिटेन पर दोष लगाया कि वह नैतिक सहारा देकर दमन को मान्यता देकर तथा मानवाधिकार का उल्लंघन कर दूसरा दक्षिण अफ्रीका बना रहा है।[46]

राष्ट्रसंघ में भी अनुदार दल की सरकार की काफी आलोचना की गयी कि उसने अल्पमत सरकार के साथ समझौता वर्तमान संवैधानिक प्रणाली के आधार पर किया। 2 जुलाई, 1971 को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें समझौते का विरोध किया गया था।

अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बिशप मुजोरेवा ने समझौते को रोडेशिया तथा ब्रितानी सरकार द्वारा एक संवैधानिक बलात्कार माना। उसने यह भी कहा कि अफ्रीकी जनता को दमनकारी एवं अत्याचारी गोरों के हाथ बेच दिया गया।

<u>स्वीकृति व सहमति की जाँच :</u>

एंग्लो-रोडेशिया समझौते के अनुसार यह समझौता तभी मान्य होना था जब रोडेशिया की पूरी जनता द्वारा स्वीकृत हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लार्ड पीयर्स की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गयी जिसका काम यह जाँच करना था कि समझौता यह जनता द्वारा "समझा गया" तथा उसे मान्य है। आयोग का काम मात्र समझौते को स्पष्ट करना व

45- एलन विंडरीच, वही, पृ0 181

46- जानु-जापु - जानु : जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन
जापु : जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल्स यूनियन।

समझाना था न कि उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए तर्क प्रस्तुत करना था ।

पीयर्स आयोग ने पिछले दशक में मोंक्टन आयोग की तरह यूरोपियनों का वरदान प्राप्त कर काम शुरू किया पर इस आयोग ने अपना फैसला अफ्रीकनों के पक्ष में दिया । अपने दो महीने के रोडेशियन जनमत के सर्वेक्षण की कार्यविधि में सभी दलों से किसी न किसी समय जल्द विदेश प्राप्त किया । इसका कार्य बहुत ही कठिन एवं अवांछनीय था क्योंकि एक पुलिस राज्य में जनमत का सर्वेक्षण करना मुश्किल था । स्मिथ का जन संचार पर पूरी तरह नियंत्रण था तथा स्मिथ ने सामान्य राजनीतिक गतिविधि के लिए बहुत कम समय निश्चित किया था । ऐसी परिस्थिति में सही जनमत जाँच का सवाल सरल नहीं था ।

समझौते के अनुसार सामान्य राजनीतिक गतिविधि की शुरुवा पर प्रतिबंध होने से बहुत हद तक अव्यवस्था फैल गयी थी । साथ ही कई दशक में यह पहली बार अफ्रीकी जनता को औपनिवेशिक शक्ति के प्रतिनिधि के सामने स्वतंत्र मत व्यक्त करने का मौका मिला था । सामान्य राजनीतिक गतिविधि की काटछाँट के बाद भी यह स्पष्ट हो गया था कि रोडेशिया की पूरी जनता एंग्लो-रोडेशिया समझौते को स्वीकार्य नहीं है । पीयर्स आयोग ने रोडेशियन फ्रंट एवं सर एलिक डगलस ह्यूम तथा लार्ड गुटमैन के समझौते के पक्ष में सभी दावों का खंडन किया । आयोग ने प्रस्तावित "अधिकार की घोषणा" को अपर्याप्त माना ।[47]

23 मई 1972 को जाँच आयोग ने परिणाम के औपचारिक घोषणा के पूर्व यह स्पष्ट हो गया था कि समझौते को अस्वीकृत कर दिया गया है । रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर इसका जबर्दस्त प्रभाव रोडेशिया तथा

47- विस्तृत विवरण के लिए देखिए - दि साउदर्न रोडेशिया सेटलमेंट प्रापोजल्स:, ह्वाय दे वर रीजेक्टेड, आब्जेक्टिव : जस्टिस, 1972, वाल्यूम 4 नं0 4, पृ0 28-29

इंग्लैंड पर पड़ा । अफ्रीकी जनता ने उल्लासित होते हुए कहा कि रोडेशिया के इतिहास में पहली बार उसके जनमत का अनुरोध अंकित एवं सम्मानित किया गया है ।

समझौते की पराजय अनुदार दल तथा उसके वार्ताकार सर एलिक डगलस ह्यूम तथा लार्ड गुडमैन की प्रतिष्ठा पर प्रहार था । इआन स्मिथ ने रिपोर्ट की कस कर आलोचना की तथा इसे गैर जिम्मेदार अवास्तविक एवं अनुचित बताया ।

पियर्स आयोग के निष्कर्ष से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी प्रकार के समझौते में अफ्रीकी जनता को सम्मिलित करना आवश्यक है । अतः अब ब्रिटेन स्मिथ को प्रोत्साहित करने लगा कि वह अफ्रीकी राष्ट्रवादियों से बातचीत करे तथा जब उसकी जरूरत होगी तब वह सहायता करेगा ।[48]

नयी वास्तविकता :

जब लेबर पार्टी पुनः 1974 में सत्ता में आयी तो उसने रोडेशियन घटना के प्रति तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया । उसने भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह अलग-थलग रहना चाहा जब तक रोडेशिया में परामर्श का दौर चल रहा हो ।

पुर्तगाल का सत्ता उलट जाने तथा पुर्तगाल उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका का माहौल पूर्ण रूप से बदल गया था । मोजाम्बीक तथा अंगोला का स्वतंत्र होना रोडेशिया के संघर्ष में एक नये घटक का जुड़ना था । अमेरिका जो अब तक अपने आप को रोडेशिया के घटनाक्रम से अलग रखे था, उसे भी मोजाम्बीक एवं अंगोला की स्वतंत्रता के बाद सम्मिलित होना पड़ा । तीसरे, चारों ओर से निराश होकर

48- डी इंग्राम- इक रोडेशिया क्रम्बल्स, राउंड टेबलनं0 256, अक्तूबर, 1979, पृ0 453

अफ्रीकी जनता गुरिल्ला युद्ध पर उतारू हो गयी ।

19 जून, 1974 को इआन स्मिथ ने संसद में घोषणा की कि आम-चुनाव 30 जुलाई को होगा जिसका मुख्य मकसद रोडेशिया में अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटना चक्र के कारण जो अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी थी उसको खत्म करना था । चुनाव में स्मिथ के जीतने की पूर्ण संभावना थी क्योंकि स्मिथ ने ऐसा ही समय निश्चित किया कि यूरोपीय विरोध तथा चुनाव का समय एक ही हो । चुनाव में अफ्रीकनों का भाग लेना अर्थहीन न था क्योंकि उन्हें मात्र आठ सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार था । साथ ही मतदान देने में बहुत सारी अड़चनें लगा दी थी । (अंततः स्मिथ ने चुनाव जीत लिया) ।

जब तक रोडेशियन फ्रंट सत्ता में रहता, अफ्रीकनों को समझौते में किसी भी प्रकार की छूट की आशा नहीं थी । इस गतिरोध को भंग करने के लिए अफ्रीकनों की एकमात्र आशा थी कि वह ब्रितानी सरकार से अपील करे । तथापि इससे भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला जैसा कि अतीत के अनुभवों से पता चलता है । 1974 में अफ्रीकनों की लेबर पार्टी से भी यही आशा थी, जो 1964 में थी जब कि चुनाव के समय "बहुमत शासन के बिना स्वतंत्रता नहीं" का प्रतिपादन किया था । टाइगर, फीयरलेस तथा ऐंग्लो-रोडेशिया समझौते के बाद किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रह गया था । लेबर पार्टी के कार्यकाल में ही "एक पक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा" की गयी तथा इसे समाप्त करने के लिए सैनिक शक्ति का भी विरोध किया गया था ।

लेबर पार्टी भी मानने लगी थी कि रोडेशियन समस्या का समाधान मात्र ब्रितानी तथा अवैध सरकार के बीच समझौते के द्वारा नहीं हो सकता। जैसा कि विदेश सचिव ने कहा कि यह ब्रितानी सरकार का काम नहीं है कि अफ्रीकनों को बताये कि किस प्रकार के समझौते का समर्थन करे । यह काम अफ्रीकनों का है वह विचार करे तथा उसके लिए काम करे । किसी भी

समझौते में अफ्रीकनों का भाग लेना अति आवश्यक है ।[49]

नरमी का वातावरण

पुर्तगाल उपनिवेशवाद की समाप्ति ने एवं रोडेशिया में बढ़ते छापामार युद्ध ने राजनयिक संधिवार्ता की शुरुआत करने में सहायता की । इस बदली परिस्थिति में जांबिया तथा दक्षिण अफ्रीका राजनयिक बातचीत का मुख्य समर्थक था क्योंकि द0 अफ्रिका के सैनिक रोडेशिया की सीमा पर सक्रिय थे तथा जाँबिया गुरिल्ला गढ़ था ।

रोडेशिया की घटना में ब्रितानी हस्तक्षेप से निराश होकर जाँबिया ने सोचा कि रोडेशिया की घटना में अवैध शासन की शक्ति के स्रोत के साथ (अर्थात द0 अफ्रीका) बातचीत करना उचित तरीका है अतः जाँबिया ने द0 अफ्रीका के साथ राजनयिक मेल-मिलाप शुरू कर दिया । दक्षिण अफ्रीका का जवाब भी सकारात्मक था और जाँबिया के राष्ट्रपति कौंडा ने इसका "विवेक की वाणी" के रूप में स्वागत किया । वोर्स्टर के उत्तर में जाँबिया के राष्ट्रपति ने "पूर्ण सैनिक छुटकारा" योजना रखी जिसमें कहा गया था कि रोडेशिया के भूभाग से दक्षिण अफ्रीका के सैनिकों को वापस लाना शांति के लिए एक पूर्व शर्त है । इसके बदले में जाँबिया अपने भूभाग तथा पड़ोसी देश तंजानिया, बोस्टवाना तथा मोजांबीक की सहायता से गुरिल्ला युद्ध का संचालन बंद कर देगा ।[50] पर यह नरमी का वातावरण अधिक दिन तक नहीं रह सका । अल्पमत एवं बहुमत रोडेशिया के बीच किसी प्रकार नहीं हो सका पर जाँबिया एवं द0 अफ्रीका द्वारा समझौते के लिए धक्का जरूर दिया गया ।[51]

49- एलन विंडरीच, वही, पृ0 236-37

50- वही, पृ0 238

51- डेविड मार्टिन और फिलिप जॉनसन समझौते का विस्तृत विवरण, पृ0 140-81

यद्यपि स्मिथ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह किसी प्रकार की बातचीत के लिए इच्छा नहीं रखता पर वह दक्षिण अफ्रीका के दबाव के कारण बातचीत के लिए तैयार हो गया । 3दिसंबर 1974 को प्रतिबंधित जानु एवं जापु दल के नेता नकोमो मुगाबे, और साइथाल को लुसाका सम्मेलन में भाग लेने के लिए रिहा कर दिया गया । पर लुसाका सम्मेलन किसी प्रकार के निष्कर्ष के बिना ही समाप्त हो गया ।

इसी समय राष्ट्रवादी नेता भी आपसी कलह एवं झगड़े को समाप्त कर एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे । जानु एवं जापु ने जो अब तक स्वतंत्र रूप से अलग-अलग कार्य कर रहे थे, अब बिशप मुजोरेवा के नेतृत्व में अफ्रीका नेशनल काउंसिल की पुनर्स्थापना की ।जोकि एकमात्र वैध संगठन रोडेशिया के अंदर था। । वे इस बात पर भी राजी हो गये कि चार महीने में एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें अफ्रीका नेशनल काउंसिल का नया संविधान अपनाया जायेगा तथा नये अध्यक्ष का चुनाव होगा ।

"नरमी का वातावरण" तथा राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा "एकता की घोषणा" ने दो तथ्यों का प्रतिपादन किया । प्रथम, स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के दबाव से अब समझौते के लिए तैयार था जो कि बहुमत शासन पर आधारित हो । दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं में एकता को अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक चलाया जा सकता है ।[52]

1974 के अंत में जेम्स कैलहन ने अफ्रीका का दौरा किया । अब यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी नेताओं का समझौते में भाग लेना अति आवश्यक है । एकपक्षीय घोषणा के बाद पहली बार इंग्लैंड की नीति में यह परिवर्तन हुआ । जुलाई 1975 में अफ्रीका एकता संगठन ने विदेशमंत्रियों की अप्रैल1975 के "दारेसलाम घोषणा" को स्वीकार कर लिया जिसमें यह कहा गया था कि शासन हस्तांतरण के लिए निष्पक्ष

52- डेविड मार्टिन एंड फिलिप्स जॉनसन, समझौते का विस्तृत विवरण, पृ0 19।

समझौते का समर्थन करेगा -- साथ ही सैनिक कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेगा । घोषणा में यह भी कहा गया कि नरमी का राजनय चालू रहेगा क्यों कि सच्चे समझौते के लिए यही एकमात्र तरीका है ।

1975 में जमैका में जब राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हुआ तब इस बात पर बहुत बहस हुई कि समझौते या सैनिक कार्रवाई का सहारा लिया जाय । इस बात पर तो सभी राजी थे कि बहुमत के शासन के बिना स्वतंत्रता की कोई संभावना नहीं है पर सैनिक कार्रवाई पर मतभिन्नता थी ।

अब तक ब्रितानी सरकार अवैध सरकार को वैध में परिवर्तित करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध का ही सहारा ले रही थी । ब्रितानी सरकार चाहे लेबर दल की हो या अनुदार दल की, हमेशा राष्ट्रमंडल राष्ट्रसंघ आदि में आर्थिक प्रतिबंध पर ही जोर देती रही । आर्थिक प्रतिबंध के उल्लंघन होने के बाद भी इंगलैंड सदा ही इसके जारी रखने के पक्ष में था । अब तक आर्थिक प्रतिबंध कोई वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं कर सका था पर 1975 में वातावरण में परिवर्तन आ चुका था जब कि रोडेशिया की परिवहन सुविधा को नियंत्रण मोजांबीक सरकार द्वारा हुआ था । रोडेशिया का आयात एवं निर्यात मोजांबीक द्वारा जब पुर्तगाल की सरकार थी तो काफी होता था पर अब अफ्रीकी जनता की सरकार होने से यह सुविधा बंद हो गयी थी । इसके बंद होने से रोडेशिया को काफी हानि थी । साथ ही मोजांबीक की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुँच रहा था । अतः मोजांबीक इस क्षति की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए हकदार था । अतः आर्थिक प्रतिबंध को चालू रखने के लिए ब्रितानी सरकार ने मोजांबीक को आर्थिक सहायता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम प्रस्तावित किया । यह ब्रितानी सरकार की रोडेशिया नीति में एक नया मोड़ था जिसका स्वागत राष्ट्रमंडल के देशों ने किया ।[53]

53- एलन विंडरीच, उपर्युक्त, पृ0 250-51

विक्टोरिया फाल्स सम्मेलन

रोडेशिया समस्या पर संवैधानिक सम्मेलन के पहले अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त था । दूसरे, स्मिथ एवं राष्ट्रवादी नेताओं में झगड़ा चल रहा था कि यह सम्मेलन रोडेशिया के अंदर हो या बाहर, दूसरी ओर राष्ट्रवादी नेता आपस में ही लड़ रहे थे । ऐसी स्थिति में अफ्रीकी देशों के राष्ट्रपति विशेष रूप से कौंडा ने हस्तक्षेप कर राष्ट्रवादियों का आपसी कलह समाप्त किया । साथ ही स्मिथ भी द0 अफ्रीका के दबाव पर राष्ट्रवादी नेताओं के बीच द0 अफ्रीका की रेलगाड़ी में विक्टोरिया फाल्स पुल पर बातचीत हुई जिसमें यह तय किया गया कि इस बैठक के बाद बातचीत कमेटी की बैठक रोडेशिया में होगी तथा इसके बाद पुनः कमेटी के प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए कहीं भी, जिस पर सभी पक्ष राजी हों, बैठक होगी ।

अफ्रीकन नेशनल काउंसिल ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था "समझौते की बातचीत की मंशा की घोषणा" इसमें पाँच बातों को सम्मिलित किया गया था :

1- अफ्रीकन नेशनल काउंसिल तथा रोडेशियन फ्रंट संवैधानिक समझौते के लिए सही इच्छा की घोषणा करनी चाहिए ।

2- दोनों दलों को सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि शासन का हस्तांतरण अल्पमत से बहुमत को होना चाहिए ।

3- दोनों दलों को सही समझौता के लिए परपीड़न एवं शक्ति का परित्याग करना चाहिए । सभी बातचीत विक्टोरिया फाल्स ब्रिज पर होनी चाहिए या दूसरी जगह जो दोनों दलों को मान्य हो ।

4- दोनों दलों को राजी होना चाहिए कि सम्मेलन का विमर्श प्राथमिक अधिवेशन द्वारा होना चाहिए । प्राथमिक अधिवेशन जरूरत होने पर कमेटी की बहाली करेगा । कमेटी की बैठक रोडेशिया के बाहर होनी चाहिए ।

स्मिथ ने तर्क प्रस्तुत किया कि औपचारिक बैठक रोडेशिया के बाहर होगी पर वास्तव पर बैठक रोडेशिया के अंदर ही होगी । दूसरी ओर राष्ट्रवादी नेताओं को रोडेशिया के अंदर भाग लेने को बाध्य नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें यह सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी थी कि रोडेशिया में आने पर उन्हें बंदी नहीं किया जायेगा । ऐसी परिस्थिति में विक्टोरिया फाल्स बैठक चौबीस घंटे के अंदर ही बिना किसी समझौते के समाप्त हो गयी ।[54]

स्मिथ-नकोमो बातचीत

जिन तथ्यों को लेकर विक्टोरिया फाल्स बातचीत समाप्त हो गयी थी उन पर पुनः स्मिथ और नकोमो के बीच वार्ता चली और 1 दिसंबर, 1975 को समझौता भी हो गया । नकोमो इस बात पर राजी हो गया कि बातचीत रोडेशिया के अंदर होगी । जब कि नकोमो रोडेशिया के अंदर सरकारी तौर पर अफ्रीकनों का नेता हो गया था तो वह इस बात के समर्थन एवं मान्यता के लिए कोशिश कर रहा था । राष्ट्रपति कौंडा ने कहा कि "यदि नकोमो द्वारा स्मिथ बहुमत शासन के लिए राजी हो जाता है तो मुजोरेवा के नेतृत्व में अफ्रीकन नेशनल काउंसिल महत्वहीन है अन्यथा यदि नकोमो सफल नहीं होता तो वह महत्वहीन है ।"[55]

इस समय नकोमो को न केवल रोडेशिया के अंदर अफ्रीकी जनता एवं काउंसिल के अन्य सदस्य जो देश के बाहर रह रहे थे, खुश करना था बल्कि अफ्रीका के अन्य देशों के राष्ट्रपतियों को भी खुश करना था । इस बातचीत से संधिकाल की सरकार पर स्मिथ राजी न हो सका ।

54- आब्जेक्टिव : जस्टिस रिसुंग, 1976, वाल्यूम 8 नं0 1, रीसेंट डेवलपमेंट इन सादर्न रोडेशिया, राष्ट्रसंघ के सचिवालय द्वारा तैयार किया गया, पृ0 24-36

55- एलन विंडरीच, रोडेशियन प्राब्लम, लंदन, 1975, पृ0 253-54

फलतः बातचीत का भंग होना अवश्यंभावी था । 19 मार्च, 1976 को नकोमो ने घोषित किया कि बातचीत भंग हो गयी तथा आगे की बातचीत व्यर्थ है ।[56]

यहाँ तक कि राष्ट्रपति न्येरेरे तथा उनके सहयोगी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत का भंग होना अति आवश्यक था क्योंकि स्मिथ मात्र समय के साथ खेल रहा है तथा समझौता ब्रितानी एवं रोडेशिया सरकार को पसंद हो सकता है पर अफ्रीकी जनता को नहीं । साथ ही इस तरह निरुद्देश्य निरंतर बातचीत राष्ट्रवादियों के बीच भ्रम पैदा कर सकती है ।[57]

56- आब्जेक्टिव : जस्टिस - स्प्रिंग - 1976, वही, पृ0 26

57- डेविड मार्टिन एंड फिलिप जॉनसन, वही, पृ0 228

अध्याय : 3

प्रत्यायन का काल

यों तो प्रत्यायन का रोडेशिया संकट में "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" के पहले से ही समस्या के समाधान के लिए प्रयोग हो रहा था पर 1974-75 से प्रत्यायन का आयाम ही बदल गया क्योंकि जिसके बारे में समाधान खोजा जा रहा था उसे ।अफ्रीकी नेता। अब संधि वार्ता में सम्मिलित किया जाने लगा जब कि पहले उसे अलग रखा जाता था। साथ ही अमेरिका, जो अब तक अलग रह रहा था, परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। प्रस्ताव की प्रस्तुति कई पक्षों की ओर से स्वीकृति-अस्वीकृति, फ्रंट लाइन स्टेट का दबाव, विश्व जनमत का प्रभाव आदि ने प्रत्यायन के क्षेत्र को बढ़ा दिया। फलतः यह प्रत्यायन का काल जिम्बाब्वे की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है।

इसी समय दक्षिण अफ्रीका में कई घटनाएँ घट रही थीं जो आगे आने वाली घटनाओं का भविष्य भी निर्धारित कर रही थीं। पुर्तगाल के उपनिवेश-- अंगोला, मोजांबीक तथा गिनी बसाऊ में सशस्त्र मुक्ति-आंदोलन सफल होने से इसका दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम पर विशेषकर जिम्बाब्वे पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ रहा था। इस विजय ने अमेरिका के इस विचार को गलत साबित कर दिया कि दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम हिंसा के द्वारा कभी भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।[58]

अंगोला तथा मोजांबीक के स्वतंत्र होने के साथ ही अफ्रीकी स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु अब रोडेशिया पहुँच चुका था जहाँ पर राष्ट्रवादी नेता अफ्रीकी

58- सी0 मुनघानु बोतलियो मूतेते- "जिम्बाब्वे एंड साउदर्न अफ्रीकन डिटांट" पृ0 61, किताब - सीटर, जॉन -"साउदर्न अफ्रीका सिन्स दि पुर्तगीज कू" ।वेस्टव्यू प्रेस - अमेरिका। 1980

बहुमत शासन के लिए संघर्षरत थे । पुर्तगाली शासन परिवर्तन के पहले रोडेशिया में समस्या के समाधान के लिए प्रगति बहुत ही कम हुई थी क्योंकि इआन स्मिथ बहुमत शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे । दूसरी ओर अफ्रीकावासी बहुमत शासन से कम कुछ भी मानने के लिए तैयार न थे ।[59]

इस बदलते परिवेश में कई राजनयिक प्रयास किये गये । दक्षिण-अफ्रीका तथा जाँबिया द्वारा अंगोला की स्वतंत्रता के बाद रोडेशिया संकट को हल करने का प्रयास किया गया । इस बार मुख्य भाग लेने वाला अमेरिका हो गया जो काफी अर्से से अलग रह रहा था । अमेरिका की इस नीति को रोबर्ट एम प्राइस ने "सौम्य तिरस्कार" कहा है । इसकी अवधि 1960 से 63 तक रही ।[60] अंगोला तथा मोजांबीक के स्वतंत्रता युद्ध ने अमेरिका को रोडेशिया में खींच लिया । अमेरिका का यह सोचा था कि इन दोनों देशों में स्वतंत्रता संग्राम सोवियत संघ की सहायता से चल रहा है । साथ ही अंगोला में क्यूबन सेना की उपस्थिति से अमेरिका को दक्षिण अफ्रीका में साम्यवाद के प्रसार का संकट नजर आने लगा । साम्यवाद को और न बढ़ने देने तथा दक्षिण अफ्रीका में सोवियत संघ की उपस्थिति को ध्यान में रखकर हेनरी किसींजर ने अपना "शटल" राजनय शुरू किया ।

59- नायर, सेरी सी0 "दी अफ्रीकन टैरेन एंड यू0 एस0 - सोवियत कॉन्फ्लिक्ट इन अंगोला एंड रोडेशिया", जार्ज, स्लेक्जेंडर §संपादित§ मैनेजिंग यू0 एस0 सोवियत राइवलरी वेस्टव्यू प्रेस §अमेरिका§ पृ0 164

60- प्राइस, रोबर्ट एम0 - "यू0 एस0 पालिसी टुवर्ड्स साउदर्न अफ्रीका : इंटैरेस्ट्स, चाइसेस, एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, पृ0 45
§किताब- कार्टर, जी0 एम0 तथा ओमेरा पी0 §संपादित§ इंटरनेशनल पालिटिक्स इन साउदर्न अफ्रीका इंडियाना यूनीवर्सिटी प्रेस, §अमेरिका§, 1982

1969 में हेनरी किसिंजर के नेतृत्व में "अफ्रीका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अंतरविभागीय समूह" (जिसमें सी0आई0ए0 गृह तथा प्रतिरक्षा विभाग सम्मिलित थे) ने अमेरिका की अफ्रीकी नीति का पुनरावलोकन किया। यह प्रसिद्ध दस्तावेज "एन0 एस0 एस0 एम0-39" के नाम से जाना जाता है जो "टार बेबी" के नाम से जाना जाता है। यह प्रलेख अमेरिका तथा किसिंजर के विवेचन का पर्दाफाश करता है। यह प्रलेख अफ्रीकावासियों की वैध आकांक्षाओं के प्रति बिल्कुल उदासीन था। जो कोई भी अपने अधिकार के लिए सशस्त्र संघर्ष में प्रयत्नशील रहा था, उसे एक खतरनाक "अस्थिर" करने वाला अभिकर्ता ही माना गया। "एन0 एस0 एस0 एम0-39" के अनुसार हर गोरिल्ला को एक आशंका माना गया जो कि सोवियत संघ तथा चीन के लिए दरवाजा खोल सकता है। "एन0 एस0 एस0 एम0-39" ने अमेरिका के पाँच नीति विकल्पों को स्पष्ट किया : 1- अफ्रीका में अमेरिकी स्थिति को बढ़ाने के तरीके पर विचार करना, 2- अमेरिका के आर्थिक, वैज्ञानिक तथा रणकला की रक्षा करना, 3- हिंसा की संभावना को खत्म करना, 4- गोरी सरकार की सख्त जातिभेद नीति तथा उपनिवेशिक विचार में नरमी लाने के लिए प्रोत्साहन तथा 5- सोवियत संघ तथा चीन के प्रभाव के अवसर को कम करना।[61]

एडगर लॉकवुड (जो अफ्रीका पर वाशिंगटन समिति के अध्यक्ष थे) ने अपने लेख "टेस्टीमोनी आन रोडेशिया एंड यू0 एस0 फारेन पालिसी" में दर्शाया है कि कैसे किसिंजर विशेष रूप से रोडेशिया पर से धीरे-धीरे प्रतिबंध में छूट की बात करने लगे तथा उन्होंने 1970 में निक्सन को सुझाया कि गृह, राजकोष एवं वाणिज्य विभाग ने प्रतिबंध में भाग लेने के लिए "कोई दूसरे तरीके" पर गौर करना शुरू कर दिया था। 1971 में निक्सन प्रशासन ने रोडेशिया में आर्थिक प्रतिबंध में भाग लेते हुए बायड समझौते के अनुसार रोडेशिया से क्रोम का आयात करने लगा। सितंबर 1973 में किसिंजर ने वायदा किया कि प्रशासन बायड समझौता को

61s मार्टिन, डेविड तथा जॉनसन, फिलिप, वही, पृ0 230-231

रद्द करने की कोशिश करेगा पर वाइटहाउस तथा किसिंजर पुनः क्रोम पर प्रतिबंध लगाने में असफल रहे । अमेरिका से जाने वाले पर्यटकों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया । इससे रोडेशिया को विदेशी मुद्रा का काफी फायदा हुआ । यह करीब पौंड 4,000,000 हर साल पर्यटन से आता था ।[62]

किसिंजर, अफ्रीकी संघर्ष को, जिसे वह "अतिवादी आंदोलन" कहता था, रोकने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था तथा इसके लिए वह अपनी रोडेशिया नीति को "नरम विकासीय सुधार के कार्यक्रम" के साथ सहयोजित करने को बताया । अर्थात वह बहुमत शासन स्वीकार तो कर रहा था पर अल्पमत के अधिकारों की भी बात करता रहा ।[63]

रोडेशिया के गोरों ने हमेशा "स्वतंत्र जगत" के समर्थन के लिए दक्षिण अफ्रीका एवं अमेरिका की ओर देखा तथा इआन स्मिथ ने अंगोला घटनाक्रम के प्रति किसिंजर के दृष्टिकोण से काफी संतोष पाया ।[64]

इस बदलते परिवेश को किसिंजर ने अमेरिका के लिए तीन तरह से नकारात्मक माना । एक, यह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जो विश्व - व्यवस्था थी उसके स्थायित्व को क्षति पहुँचा रहा था । दूसरे, अमेरिका द्वारा विश्व व्यवस्था को बनाये रखने की अमेरिकी इच्छा तथा योग्यता को इससे क्षति पहुँच रही थी । तीसरे, यह अतिवादी आंदोलन को प्रोत्साहित हो रहा था जो कि यूरोपीय स्वार्थों को खतरा बढ़ा रहा था ।[65]

किसिंजर के हस्तक्षेप से "नरमी का कार्य" का स्थान "शटल राजनय" ने ले लिया । किसिंजर ने कई अफ्रीकी देशों की समस्या के समाधान के लिए भ्रमण करना शुरू कर दिया । उसने पहले अफ्रीकी राज्य विशेषकर

62- मार्टिन, डेविड तथा जॉनसन, फिलिप, वही, पृ0 231-32
63- वही, पृ0 235
64- वही, पृ0 236
65- प्राइस, रोबर्ट एम0 - वही, पृ0 48

जाँबिया तथा तनजानिया की सलाह लेकर फिर दक्षिण अफ्रीका से परामर्श किया । "नरम प्रयास" में दक्षिण अफ्रीका स्मिथ पर प्रभाव डालने वाला वही मुख्य अभिनेता था चूँकि रोडेशिया का बाहरी दुनिया से संपर्क दक्षिण अफ्रीका द्वारा ही होता था ।[66]

किसिंजर का दक्षिण अफ्रीका में दस दिनों का शांति मिशन 14सितंबर, 1976 से शुरू हुआ, जो राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे से तथा अन्य फ्रंट लाइन राज्यों के राष्ट्रपतियों से मिला । इआन स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के दबाव के कारण अमेरिका की शांति योजना, जो "किसिंजर के पैकेज" के नाम से जानी जाती है, को स्वीकार किया । स्मिथ ने अपने प्रसारण भाषण में कहा कि मैं बहुमत शासन के लिए राजी हूँ पर यह एक"उत्तरदायी शासन" होना चाहिए । स्मिथ के अनुसार, "उत्तरदायी शासन का अर्थ था कि बहुमत गोरे का हो पर नरमपंथी अफ्रीका नेता को भी शामिल किया जाये जो गोरों के साथ रहने के लिए तैयार हो ।[67]

इआन स्मिथ ने किसिंजर की शांति योजना का जो ब्योरा 24 सितंबर, 1976 को घोषित किया वह इस प्रकार था :

1- रोडेशिया शासन दो वर्षों में बहुमत के शासन के लिए तैयार है ।
2- रोडेशिया सरकार के प्रतिनिधि जल्द ही अफ्रीकी नेता से आपसी विचार विमर्श के बाद निश्चित स्थान पर मिलेंगे जिसमें बहुमत शासन लागू होने के पूर्व काल में अंतरिम काल के लिए बातचीत करेगा ।
3- अंतरिम शासन में राज्य परिषद एवं राज्य मंत्रिमंडल होगा । राज्य परिषद में आधे सदस्य अफ्रीकी होंगे तथा आधे श्वेत होंगे । अध्यक्ष श्वेत होगा पर उसे कोई भी विशेष अधिकार नहीं होगा । अफ्रीकी तथा गोरों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होंगे जो विधान का

66- एलन पिंडरीच, पृ0 261

67- वही, पृ0 262

संशोधन, सामान्य निरीक्षण की जिम्मेदारी तथा संविधान के दक्षता का निरीक्षण करेंगे । मंत्रिपरिषद में अफ्रीकावासियों का बहुमत होगा तथा प्रधानमंत्री अफ्रीकी होगा । संक्रांतिकाल में प्रतिरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था एक गोरे मंत्री के अधीन होगी । मंत्रिपरिषद का निर्णय दो तिहाई बहुमत द्वारा होगा ।

4- ब्रितानी सरकार कानून बनायेगी जो बहुमत शासन की प्रक्रिया को सरल करेगा । इस कानून के बनने के बाद रोडेशिया का शासन ऐसा विधान बनायेगा जो इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा ।

5- अंतरिम शासन की स्थापना के बाद आर्थिक प्रतिबंध हटा दिया जायेगा तथा युद्ध यहाँ तक कि गुरिल्ला युद्ध भी बंद कर दिया जायेगा ।

6- अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा रोडेशिया के आर्थिक विकास के लिए "आर्थिक सहायता"दी जायेगी । यह सहायता निम्नलिखित होगी :

क- रोडेशिया के बाहर एक "विकसित कोष" स्थापित किया जायेगा जो देश में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा । यह कोष देश में बहुत सारी प्रयोजनाओं के विकास गारंटी एवं निवेश के लिए आंतरिक एवं बाह्य आर्थिक नीति का सहयोग करेगा । इस कोष का मुख्य उद्देश्य देश में उद्योग एवं खनन, कृषि का विकास तथा साथ ही आवश्यक कुशलता के लिए आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर की व्यवस्था करना होगा ।

ख- व्यक्तिगत पेंशन अधिकार, गृह, फार्म निवेश तथा प्रेषित रुपया, एक निश्चित सीमा तक विदेशी संपदा आदि का अंतरिम तथा उसके बाद की सरकार द्वारा गारंटी दी जायेगी ।[68]

68- आब्जेक्टिव : जस्टिस-एटेम्प्ट एट ए पीसफुल सेटलमेंट इन साउदर्न रोडेशिया ।राष्ट्रसंघ सचिवालय द्वारा प्रस्तुत पेपर।पृ0 19, वॉल्युम 9 नं0 1, स्प्रिंग- 1977

किसिंजरयोजना पर प्रतिक्रिया एवं विश्लेषण :

इस एंग्लो-अमेरिकन पहल पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई । इस योजना पर फ्रंट लाइन राज्यों ।अंगोला, बोत्स्वाना, मोजांबीक, तन्जानिया तथा जांबिया। के राष्ट्रपतियों ने लुसाका में एक बैठक की । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अमेरिकी योजना अवश्य: औपनिवेशिक एवं रंगभेद की शक्ति को वैधता प्रदान करती हैं । इन लोगों ने ब्रितानी सरकार से कहा कि रोडेशिया के बाहर एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाया जाये जिसमें संक्रांति काल की सरकार तथा स्वतंत्र रोडेशिया के संविधान के लिए परिचर्चा की जाये ।

राष्ट्रवादी नेता मुजोरेवा नकोमो तथा मुगाबे ने किसिंजर योजना को अमान्य समझा । उन लोगों ने, विशेष रूप से मंत्रिमंडल के अधिकार एवं गठन और प्रतिरक्षा, कानून एवं व्यवस्था विभाग को गोरों के हाथ में रखने का प्रतिरोध किया । दो वर्ष का संक्रांतिकाल भी काफी लंबा माना । इन नेताओं ने उन प्रस्तावों का भी प्रतिरोध किया जिनमें गोरों को आर्थिक गारंटी की बात की गयी थी ।

वस्तुतः किसिंजर योजना का मुख्य उद्देश्य गोरों के स्वार्थों की ही रक्षा करना था । इसकाप्रमाण तीन बातों से मिलता है :

1- प्रतिरक्षा, कानून एवं व्यवस्था विभाग, जो किसी भी देश की सरकार के मुख्य विभाग होते हैं, गोरों के हाथ में रखे जाने थे जो आसानी से अफ्रीकियों के विरुद्ध इसका दुरुपयोग कर सकते थे ।

2- मंत्रिपरिषद में अफ्रीकीयों का बहुमत तो था जिससे ऐसा लगता था कि बहुमत शासन की बात की गयी है पर किसी भी निर्णय में गोरों का समर्थन आवश्यक था । निर्णय के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी ।

3- गोरों को काफी आर्थिक अधिकार दिये गये थे तथा इनकी गारंटी की बात की गयी थी ।

स्पष्ट है यदि किसिंजर शांति योजना को स्वीकार किया जाता तो इसका अर्थ औपनिवेशिक तथा रंगभेद की नीति को वैधता देना ही होता।

जेनेवा सम्मेलन

फ्रंट लाइन राष्ट्रपतियों की मुलाकात घोषणा तथा सुझाव पर ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल के सचिव कालैंड ने 29 सितंबर 1976 को घोषणा की कि उनकी सरकार मुलाकात सुझाव, जिसमें संक्रांतिकाल तथा संविधान के लिए एक सम्मेलन की बात की गयी थी, को स्वीकार करता है। इसके दो दिन के बाद नकोमो तथा मुगाबे दोनों ने मिल कर "पेट्रियाटिक फ्रंट" का निर्माण करने की घोषणा की। पेट्रियाटिक फ्रंट ने दो प्रतिनिधि भेजे तथा निम्न सुझाव दिये :

क- अफ्रीकी नेता को ठीक ढंग से तैयार होने के लिए और समय मिलना चाहिए। कम से कम दो सप्ताह के लिए जेनेवा सम्मेलन स्थगित कर देना चाहिए।

ख- शक्ति का हस्तांतरण जल्द ही अफ्रीकी बहुमतियों के हाथ में करना चाहिए।

ग- सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देना चाहिए।

घ- सभी "सुरक्षित" गाँवों को समाप्त कर देना चाहिए।[69]

उधर स्मिथ ने किसिंजर योजना को अपनी व्याख्या के अनुसार स्वीकार किया। स्मिथ के अनुसार जेनेवा सम्मेलन का यह उद्देश्य था कि वह इस बात पर विचार करे कि किसिंजर योजना को कैसे लागू किया जाये। स्मिथ ने किसिंजर योजना में कपट का रास्ता देखा। स्मिथ ने कहा कि किसिंजर ने मुझसे वादा किया कि राष्ट्रवादी नेताओं के असहयोग के कारण यदि जेनेवा सम्मेलन भंग हो जायेगा तो उसकी सरकार को आर्थिक सहायता दी जायेगी। अमेरिकी सरकार ने

69- आब्जेक्टिव : जस्टिस, वही, पृ0 20

इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया कि किसिंजर ने इस प्रकार का वादा किया ।

जेनेवा सम्मेलन की बैठक राष्ट्रसंघ में ब्रितानी सरकार के स्थायी सदस्य आइवोन रिचर्ड के नेतृत्व में 28 अक्तूबर 1976 को शुरू हुई । इस बैठक में मुगाबे, नकोमा, मुजोरेवा तथा इआन स्मिथ ने भाग लिया । सामान्य बातचीत के बाद सम्मेलन में संक्रांतिकाल के समय पर विचार किया गया । अफ्रीकी नेताओं ने संक्रांतिकाल का समय एक साल माना अर्थात 1 दिसंबर 1977 तक । अवैध सरकार ने संक्रांतिकाल एक साल ग्यारह महीने का अर्थात नवंबर 1978 तक का प्रस्ताव रखा । ब्रितानी सरकार ने एक साल चार महीना अर्थात मार्च 1978 तक माना ।

अंतरिम सरकार की बनावट पर अफ्रीकी प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि ब्रितानी सरकार को एक राज्यपाल या आयुक्त भेजना चाहिए जो संक्रांतिकाल में शक्ति के हस्तांतरण के लिए काम करे । साथ ही इन लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के लिए माँग रखी ।

दूसरी ओर, स्मिथ किसी भी प्रकार के प्रस्ताव रखने से पीछे हट गया और इस पर जोर देता रहा कि अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए किसिंजर योजना को ही माना जाये । बिना किसी प्रगति के जेनेवा सम्मेलन स्थगित कर दिया गया तथा आशा की गयी कि इसे पुनः जनवरी 1977 में बुलाया जायेगा ।[70]

सम्मेलन के भंग होने पर यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी प्रकार के समझौते के लिए सभी पक्षों का राजी होना आवश्यक है । अतः ब्रितानी सरकार ने अफ्रीकी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद एक "नया प्रस्ताव" रखा जिसमें संक्रांतिकाल में ब्रितानी सरकार के भाग लेने की बात कही गयी । यह व्यवस्था प्रस्तावित की गयी कि प्रतिरक्षा कानून एवं व्यवस्था

70- जाब्जेविट्स, जस्टिस - वही, पृ0 20-21

विभाग "राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद" द्वारा नियंत्रित होंगे जिनमें अफ्रीकी तथा गोरे होंगे और किसी प्रकार का गतिरोध होने पर अंतिम निर्णय आवासी आयुक्त का होगा। पर इस नये प्रस्ताव को भी स्मिथ ने नामंजूर कर दिया।

<u>डेविड ओवेन तथा एंड्रू यंग योजना :</u>

1977 के अंत तक स्मिथ इस बात को स्वीकार करने लगा कि अफ्रीकी शासन अपरिहार्य है। इसका कारण गुरिल्ला युद्ध के कारण बढ़ते खर्च[71] या दक्षिण अफ्रीका के बढ़ता दबाव थे।

अगस्त 1977 में राष्ट्रपति न्येरेरे ने जब अमेरिका का भ्रमण किया था वे तब कार्टर से मिले और शीघ्र ही अमेरिका तथा इंग्लैंड ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि "रोडेशियन सुरक्षा सेना" को ब्रितानी आवास आयुक्त के नियंत्रण में रखा जायेगा जिससे बदनाम "सेलुस स्काउट" को कुछ हद तक प्रतिबंधित कर दिया जायेगा तथा "जिम्बाब्वे सेना" का निर्माण गुरिल्ला तथा रोडेशियन सेना से किया जायेगा।[72]

ब्रितानी विदेश सचिव डेविड ओवन तथा राष्ट्रसंघ में अमेरिकी दूत एंड्रू यंग ने एक योजना रखी। इस योजना के अनुसार गोरी सरकार वैसे ही सेना पर नियंत्रण त्याग देगी, वैसे ही गुरिल्ला द्वारा युद्धविराम रेखा को स्वीकार कर लिया जायेगा। रोडेशिया फ्रंट की सरकार शासन को आवास आयुक्त लार्ड कारवर के सुपुर्द कर देगी जो संक्रांति काल में गोरी सेना के नयी सेना में परिवर्तन का निरीक्षण करेंगे।[73]

स्मिथ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उसने सोचा कि यदि एक बार गोरी सेना को दुर्बल कर दिया गया तो नकोमो और मुगाबे जैसे गुरिल्ला नेता गोरों के स्वार्थ की उपेक्षा कर सकते हैं।

71- जॉन डे, - वर्ल्ड टुडे ।लंदन। दी रोडेशियन इंटरनल सेटलमेंट, जुलाई, 1978, पृ0 271

72- एलन पिंडरीच - दी एंग्लो अमेरिकन इनेशियेटिव : एन इंटरिम एसेसमेंट वर्ल्ड टुडे ।लंदन। वाल्यूम 25, जनवरी-दिसंबर 1978, पृ0 299

73- जॉन डे - वर्ल्ड टुडे, उपर्युक्त, पृ0 272-73

आंतरिक समझौता

जेनेवा सम्मेलन की असफलता के बाद यह स्पष्ट हो गया कि स्मिथ उसी अफ्रीकी नेता से संधिवार्ता करेगा जो गुरिल्ला युद्ध से अपने आप को अलग रखता हो तथा शांतिपूर्ण समझौता चाहता हो। जेनेवा सम्मेलन के बाद दो ब्रितानी प्रस्ताव रखे गये जो अमेरिका द्वारा समर्थित थे। इनसे किसी प्रकार का समाधान न हो सका। इन प्रस्तावों से यह बात और भी स्पष्ट हो गयी कि स्मिथ अफ्रीका नेता से संधिवार्ता बिना किसी बाहरी सहयोग से करेगा। अफ्रीकी नेता से संधि करने का स्मिथ का मुख्य उद्देश्य एक तो गोरे वासी के हितों की रक्षा करना तथा बहुमत शासन स्वीकार करनाथा, दूसरे अफ्रीकी राष्ट्रवादियों में फूट डालना जिससे कि बहुमत शासन में देर लग सके।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो अफ्रीकी नेता साइथोल तथा बिशप मुजोरेवा को उसने आंतरिक संधि के लिए राजी कर लिया। स्मिथ ने कहा कि न तो हमें ।स्मिथ। और न तो साइथोल एवं मुजोरेवा को एंग्लो अमेरिकन योजना के अनुसार जिम्बाब्वे की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दोनों का उद्धार आपसी फायदे से है। इन अफ्रीकी नेताओं ने गोरों पर भरोसा स्वीकार किया तो स्मिथ ने एक व्यक्ति एक मत को स्वीकार किया। एवं इन अफ्रीकी नेताओं के बीच मार्च 1978 में संधि हुई, जो "सेलिसबरी संधि" या "आंतरिक समझौता" के नाम से जानी जाती है।

"आंतरिक समझौता" की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं :

1- नये संविधान का आधार व्यापक वयस्क मताधिकार होगा।

2- सभी पदाधिकारी अब तक जो रोडेशिया सरकार में काम कर रहे हैं, को उनकी नौकरी तथा पेंशन की गारंटी 10 वर्षों तक दी जायेगी।

3- नागरिक सेवा, पुलिस एवं प्रतिरक्षा का स्तर एवं कुशलता बरकरार रखे जायेंगे तथा यह राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रहेंगे। इसका अर्थ था यह सब गोरों के अधीन ही रहेंगे।

4- प्रस्तावित सम्मेलन में 100 सदस्य होंगे जिनमें 28 गोरे होंगे। 17 सदस्यों के मंत्रिमंडल में 6 सदस्य गोरे होंगे।

5- रोडेशिया में द्वि-स्तरीय सरकार होगी। सबसे ऊपर चार सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद होगी जिसमें एक गोरा रहेगा। नीचे के स्तर पर मंत्रिपरिषद होगा जिसमें 9 अफ्रीकी एवं 9 गोरे वासी होंगे।

6- स्मिथ तथा वर्तमान संसद संक्रांति काल की देख-रेख करेगा। यह संक्रांतिकाल 31 दिसंबर 1978 तक रहेगा। बाद में सुधार कर 31 मई, 1978 कर दिया गया।।[74]

आंतरिक समझौते का विश्लेषण

आंतरिक समझौते का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं :

1- प्रस्तावित सम्मेलन में स्थानों का बंटवारा उचित नहीं था। 100 सदस्यों के सम्मेलन में गोरों को 28 सुरक्षित स्थान दिये गये जो कि उसकी जनसंख्या से 18 प्रतिशत ज्यादा थे। 10प्रतिशत जनसंख्या के मुताबिक गोरे 10 स्थानों के लिए भागीदार थे।

2- सम्मेलन में 72 स्थान जो अफ्रीकी अधेतों को दिये गये थे उनमें उसके लिए चुनाव काले तथा गोरे के संयुक्त मतों द्वारा होना था पर गोरे के 28 स्थानों के लिए केवल गोरे ही भाग ले सकते थे। यह एक असह्य भेदभाव था। अर्थात अफ्रीकी को निर्वाचित होने के लिए काले का सहारा लेना आवश्यक था।

3- समझौते में चार सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद की बात की गयी थी जिसमें एक गोरे का होना आवश्यक था। इसमें निर्णय बहुमत के

74- आंतरिक समझौते का विस्तृत वर्णन देखें : अफ्रीकन रिकार्ड, वाल्यूम XVIII नं0 7, मार्च 26 अप्रैल 1978, पृ0 4764-65

स्थान पर सहमति की व्यवस्था की गयी थी । इसका अर्थ था किसी भी बात में गोरे का समर्थन आवश्यक था । बहुमत का शासन मात्र एक छलावा था ।

4- मंत्रिपरिषद में 9 मंत्री अफ्रीकी होने थे तथा 9 गोरे । इसका मतलब था एक विभाग में दो मंत्री । हर निर्णय में गोरे मंत्री का समर्थन लेना आवश्यक था ।

5- "विशेष मोर्चाबंदी प्रस्ताव" का जिक्र भी किया गया था । इस प्रावधान के अनुसार संविधान में किसी भी प्रकार के लिए सम्मेलन में 78 सदस्यों का समर्थन जरूरी था । अफ्रीकी सदस्य मात्र 72 थे । इसका अर्थ था 6 गोरे सदस्यों का सहयोग आवश्यक था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अफ्रीकावासी बहुमत होने के बाद भी किसी प्रकार का संशोधन करने में बिना गोरे की सहायता से असमर्थ थे । यह विशेष व्यवस्था आधुनिक संविधान संशोधन की प्रथा से बिल्कुल भिन्न थी ।

6- अफ्रीका वासी इस "विशेष मोर्चाबंदी प्रस्ताव" को भी संशोधित नहीं कर सकते थे । यह व्यवस्था 10 वर्षों तक जारी रहती । इसके समाप्त होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाना था जो इसका पुनरावलोकन करता ।

7- आंतरिक समझौते के अनुसार "अधिकार के न्यायपूर्ण घोषणा" की बात कही गयी थी जिसके अनुसार व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा की जानी थी । इसके अनुसार गोरों को पेंशन के अधिकार की रक्षा की जायेगी । यह प्रस्ताव सिर्फ इसलिए जोड़ा ताकि गोरों की सम्पत्ति के अधिकार को अक्षत रखा जा सके ।

8- समझौते के अनुसार न्यायालय के लिए विशेष स्वतंत्रता एवं अहर्ताओं की व्यवस्था की गयी थी तथा जजों का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया था । इसका अर्थ था कि गोरे लोग काफी दिनों तक जज बने

रहेंगे क्योंकि अफ्रीकावासी बहुत कम शिक्षित एवं न्यायविद थे । इस प्रकार गोरों का प्रभाव न्यायालय में भी बना रहता ।

इन सब तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि बहुमत का शासन मात्र भ्रम एवं धोखा था । इस समझौते से सिर्फ स्मिथ के कई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी ।[75]

बहुमत के नाम पर इआन स्मिथ ने तीन अफ्रीकी नेताओं से गोरों के हितों की रक्षा के लिए काफी रियायतें हासिल कर लीं थीं । पहले तो अफ्रीकावासी गोरों द्वारा शोषित होते थे पर आंतरिक समझौते के अनुसार अफ्रीकी जनता का शोषण नेता द्वारा गोरे लोग करने लगे ।[76] आंतरिक संधि को "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" के अंदर इसे एक और स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" कहा जाने लगा । मुजोरवा ने अफ्रीकी हितों को गोरों के हाथों बेच दिया । रॉबर्ट मुगाबे ने तो मुजोरवा की बुरी तरह आलोचना की। उसने कहा - "यह एक मस्तिष्क का परिवर्तन है । गोरे के स्थान पर काले को ला दिया । पर शरीर वही है, सेना, नागरिक सेवा, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सब वही पुरानी है ।"

आंतरिक समझौता, एक समझौता न होकर मात्र झगड़ा बढ़ाने तथा समस्या को और गंभीर करने का एक नुस्खा था । स्मिथ ने समझा कि पुराना तरीका उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा सकता अतः उसने नये छल एवं तरीके को अपनाया । जो कि एक तीर से कई को घायल कर रहा था । हालांकि नये तरीके को अपना लिये पर समस्या वही पुरानी थी । किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था ।[77]

75- जॉन डे, वही पृ0 273

76- के0 न्यामायाओ मुफुका-"रोडेसियाज इंटरनल सेटलमेंट : ए ट्रेजेडी" अफ्रीका एफेयर्स ।आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, लंदन। वाल्यूम 78, नं0 313, पृ0 439-50, अक्तूबर 1979

77- सलीम ए0 सलीम ।उपनिवेश के विरुद्ध 24 देशों की विशेष सभा के अध्यक्ष। "दि इंटरनल सेटलमेंट इन रोडेसिया" आब्जेक्टिव : जस्टिस- वाल्यूम 10, नं0 1, स्प्रिंग 1978, पृ0 6

अब प्रश्न उठता है कि स्मिथ अपने उद्देश्यों में क्यों सफल हुआ ?

प्रथम, यह बात बिल्कुल सही है कि स्मिथ समझौता करने में एक प्रबुद्ध व्यक्ति था । वह बदलती परिस्थितियों की आसानी से नब्ज पकड़ लेता था । वह अपने "देर करने का तरीका तथा उसे जीवित भी रखा जाये" में माहिर था ।[78]

दूसरे, अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेताओं ने लगातार आपसी झगड़ों एवं कलह में घिरे रहे जिससे कि बहुत हद तक गोरों को शासन करने में सहायता मिली । गोरे आसानी से "फूट डालो और शासन करो" की नीति में सफलता पाते रहे । छोटी-छोटी बातों को अफ्रीकी नेता बड़े उद्देश्य के लिए सुलझाने के लिए तैयार नहीं थे । आपसी जातीय अंतर को भुलाने में असमर्थ थे । अपनी नीति के बारे में राष्ट्रवादी नेता बहुत ही कम विभिन्न थे पर आपसी कलह के ऊपर विजय पाने में असमर्थ थे ।[79]

तीसरे, यह कि अफ्रीकी नेता काफी महत्वाकांक्षी थे । उन लोगों में होड़ थी कि कौन सबसे पहले काला प्रधानमंत्री बन सकता है । रोडेशिया में कोई भी अफ्रीकी नेता ऐसे न था जो कि केन्याटा, नुकरोमाह, न्येरेरे या मैकेल की तरह हों ।[80] रोडेशिया में सभी राष्ट्रवादी नेता किसी न किसी समय गोरे शासन से बातचीत इस उद्देश्य से की कि वह सबसे पहले प्रधानमंत्री बने ।

78- एलन विंडरीच - वर्ल्ड टुडे, वही, पृ0 296

79- जॉन डे- "दी डिवीजन आफ दी रोडेशियन अफ्रीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट", वर्ल्ड टुडे - वाल्यूम 23, नं0 10, पृष्ठ 385

80- रोनाल्ड एल0 सीची - ऐंग्लो-अमेरिकन डिप्लोमेसी एंड दी रोडेशियन सेटलमेंट : ए लॉस आफ इमोटल आरविस ।अमेरिका।- वाल्यूम 23, नं0 1, स्प्रिंग 1979, पृ0 192

मुजोरवा की दुविधा

समझौते के अनुसार अप्रैल 1979 में चुनाव हुआ । इस चुनाव में मुजोरवा विजयी रहा और प्रथम अफ्रीकी प्रधानमंत्री बना । आंतरिक समझौते की राष्ट्रसंघ, राष्ट्रमंडल, अफ्रीकी एकता संगठन, फ्रंट लाइन राज्य आदि की आलोचना के बाद भी दक्षिण अफ्रीका ने चुनाव के निरीक्षण के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजा ।

रोडेशिया में जो अप्रैल 1979 में चुनाव हुआ उस पर तीन रिपोर्टें प्रकाशित हुई : 1- बॉयड रिपोर्ट जो अनुदार दल द्वारा भेजी गयी एक टीम की थी, 2- BTO क्लेयर पुले द्वारा, 3- लार्ड चिटनीस द्वारा । एक ओर बॉयड द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट तथा दूसरी ओर BTO क्लेयर पुले और लार्ड चिटनीस द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्टें बिल्कुल भिन्न थीं तथा दोनों के निष्कर्ष भी अलग-अलग थे ।

बॉयड रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष था । बड़ी संख्या में, करीब 62 प्रतिशत जनता ने, चुनाव में भाग लिया जो दर्शाता है कि संवैधानिक आधार पर किया गया यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

बॉयड रिपोर्ट का पूर्ण रूप से BTO क्लेयर पुले तथा लार्ड चिटनीस द्वारा खंडन किया गया । इन लोगों का कहना था कि किसी भी चुनाव तरीके से यहाँ तक कि विकसित देशों की चुनाव प्रणाली के अनुसार भी रोडेशिया का चुनाव न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष था । इन लोगों का कहना था कि मतदाताओं को डराया एवं धमकाया गया । गलत ढंग से प्रचार किया गया । यह जनमत जाँच करने का सही तरीका नहीं था अतः चुनाव महत्वहीन था ।[81]

81= मीक दीपेल- (बीबीसी अफ्रीकन सेवा का एक सदस्य) 2 अप्रैल, 1979 इलेक्शन इन जिम्बाब्वे - रोडेशिया अफ्रीकन अफेयर्स (ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, लंदन), वाल्यूम 78 नं0 313, पृ0 431-32

अब मुजोरवा सरकार के सामने दो ही उद्देश्य थे -- एक किस प्रकार विश्व के सभी देशों से जिम्बाब्वे रोडेशिया के लिए मान्यता प्राप्त की जाये और दूसरा, कैसे आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त किया जाये । दो प्रकार की चुनाव रिपोर्ट के कारण मुजोरवा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका । विश्व द्वारा मान्यता न प्राप्त करने तथा आर्थिक प्रतिबंध के समाप्त न होने का अर्थ था कि रोडेशिया का दक्षिण अफ्रीका पर और भी अधिक निर्भर रहा । अपनी विदेशी नीति में असफल होने के बाद मुजोरवा को कठिन आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा । आंतरिक समझौता के अफ्रीकी भागीदार साइथोल ने संसद का बहिष्कार यह कह कर किया कि 1979 के चुनाव में काफी धांधलेबाजी हुई । साथ ही आंतरिक समझौता के तीसरे सदस्य चिरेमा ने भी सरकार को नये दल बनाने के उद्देश्य से तोड़ दिया ।

इस बीच इंगलैंड में अनुदार दल श्रीमती थैचर के नेतृत्व में पुनः सत्ता में आया । बॉयड रिपोर्ट के आधार पर जिम्बाब्वे रोडेशिया को मान्यता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध था । अब मुजोरवा के सामने मात्र श्रीमती थैचर के वक्तव्य की ही एकमात्र आशा रह गयी थी । राष्ट्रमंडल देशों के लुसाका में सम्मेलन होने के चार सप्ताह पहले श्रीमती थैचर ने कैनबरा में कहा कि वह जिम्बाब्वे रोडेशिया पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगायेगी पर मान्यता देने के लिए लंबा समय लग सकता है ।[82]

श्रीमती थैचर को जिम्बाब्वे रोडेशिया को मान्यता प्रदान करने में कोई बाधा थी तो वह अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति थी । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर पहले के ऐंग्लो-अमेरिकन योजना पर ही वचनबद्ध थे । अफ्रीकी एकता संगठन ने मुजोरवा को मान्यता प्राप्त करने से इंगलैंड को मना किया । फ्रंट लाइन के देशों ने भी श्रीमती थैचर के वक्तव्य का खंडन किया । दारेसलाम की बैठक 12 जून, 1979 में फ्रंट लाइन राज्यों ने कहा कि यदि

82- दी इकानामिस्ट (लंदन) 7 जुलाई, 1979

लंदन मुजोबा सरकार को मान्यता देता है तो ब्रितानी सरकार का संबंध अफ्रीकी देशों के साथ खराब हो जायेगा।[83] राष्ट्रमंडल के देशों ने भी कहा कि श्रीमती थेचर की एकपक्षीय मान्यता का हम लोग विरोध करेंगे। विश्वव्यापक विरोध के कारण श्रीमती थेचर ने मुजोबा सरकार को मान्यता नहीं दी। अपने कैनबरा वक्तव्य से अलग होते ही श्रीमती थेचर ने कहा, जिम्बाब्वे रोडेशिया का संविधान कुछ मामलों में दोषपूर्ण है। गोरों के शासन की भर्त्सना एवं बनावट की आलोचना को श्रीमती थेचर ने प्रामाणिक माना। साथ ही समस्या के समाधान के लिए पेट्रियाटिक फ्रंट का शामिल होना आवश्यक माना।[84]

लुसाका में राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन

जिम्बाब्वे की समस्या के समाधान के लिए ब्रितानी सरकार ने लुसाका सम्मेलन में अपने पूर्व घोषित नीति में सुधार किया। रोडेशिया में वास्तविक अफ्रीकी बहुमत शासन तथा उपनिवेश की स्वतंत्रता जो विश्व-समुदाय को मान्य हो, के लिए श्रीमती थेचर ने घोषणा की। राष्ट्रमंडल तथा फ्रंट लाइन राज्य के भी मुख्य नेता श्री कौंडा ।जांबिया के राष्ट्रपति। तथा न्येरेरे ।तंजानिया के राष्ट्रपति। से ब्रितानी सरकार ने प्रार्थना की कि सही समस्या के समाधान के लिए सहयोग करें। दोनों राष्ट्रपति लंदन की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए दोहरे उद्देश्यों से तैयार थे। गुरिल्ला युद्ध तथा आर्थिक प्रतिबंध के कारण तंजानिया तथा जांबिया की अर्थव्यवस्था को काफी हानि पहुंच रही थी। दोनों राज्यों ने, विशेषकर जांबिया ने, एकपक्षीय घोषणा के बाद से ही काफी त्याग

83- केतीगन कंटिम्पोररी आइकाइव्स ।लंदन। वाल्यूम 25 10 अगस्त 1979, पृ0 29761

84- मार्टिन ग्रेगोरी - "झोडेशिया : फ्राम लुसाका टू लैनकास्टर हाउस" वर्ल्ड टुडे ।लंदन। वाल्यूम नं0 36, नं0 1, पृ0 13

किया । तनजानिया और जाँबिया ब्रितानी सरकार के प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इतनिए तैयार थे कि इससे उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल रही थी, दूसरे इससे उसके उपनिवेशी विरोधी नीति को भी खतरा नहीं पहुंच रहा था ।[85] जहाँ तक रोडेशिया समस्या का प्रश्न है लुसाका सम्मेलन एक खास महत्व का था । इस सम्मेलन ने समस्या के समाधान को एक खास मोड़ दिया । सम्मेलन का सभापतित्व राष्ट्रपति डा० कौंडा द्वारा किया गया । राष्ट्रवादी नेता मुख्य रूप से मुगाबे और नकोमो के विरोध के बाद भी उसे फ्रंट लाइन राज्य, अफ्रीकी एकता संगठन, अमेरिका तथा राष्ट्रमंडल देशों के दबाव के कारण अंतिम निर्णय स्वीकार करना पड़ा । लुसाका सम्मेलन की निम्न घोषणा थी :

रोडेशिया की स्थिति से संबंधित राष्ट्रमंडल के देश :

1- निश्चित करते हैं कि वे लोग जिम्बाब्वे की जनता के लिए वास्तविक बहुमत शासन के लिए वचनबद्ध हैं।

2- मानते हैं कि आंतरिक समझौते में महत्वपूर्ण मामले में दोष है ।

3- पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि बहुमत शासन के आधार पर जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता प्रदान करने का ब्रितानी सरकार को संवैधानिक अधिकार है ।

4- मानते हैं कि पूर्ण शांति के लिए झगड़े से संबंधित सभी पक्षों का सम्मिलित होना आवश्यक है।

5- इस प्रकार के समझौते की सफलता तथा जिम्बाब्वे की जनता तथा उसके पड़ोसी देशों के लिए ये लोग बहुत चेतन हैं ।

6- स्वीकार करते हैं कि बहुमत के आधार पर प्रजातंत्र के लिए प्रजातांत्रिक संविधान की आवश्यकता है जिसमें अल्प जनसंख्यक की भी रक्षा की जाये।

85- मार्टिन ग्रेगोरी, उपर्युक्त, पृ० 14

7- स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार के स्वतंत्र संविधान में सरकार का गठन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार पर हो जो कि ब्रितानी सरकार के उचित निरीक्षण में हो तथा राष्ट्रमंडल के देश प्रेक्षक हों ।

8- ब्रितानी सरकार के संकेत का स्वागत करते हैं कि इन उद्देश्यों के विकास के लिए एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाया जायेगा जिसमें सभी पक्षों को आमंत्रित किया जायेगा ।

9- फलतः स्वीकार करते हैं कि टिकाऊ शांति के लिए आपसी विद्वेष तथा प्रतिबंध को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ।[86]

इस प्रकार लुसाका सम्मेलन में रोडेशिया पर अंतिम संयुक्त विज्ञप्ति अपने आप में काफी महत्व रखती है । इसी के बाद रोडेशिया की स्वतंत्रता की बात स्पष्ट हो गयी थी । पर यह सम्मेलन मुजोरेवा के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा था । इसलिए मुजोरेवा ने लुसाका सम्मेलन में कहा कि यह एक निर्वाचित समूह तथा जिम्बाब्वे रोडेशिया सरकार का अपमान है । गोरे के हितों की रक्षा करने वाला समाचारपत्र "दी हैराल्ड" ने श्रीमती थैचर को कहा कि वह "महाजाल में डेविड ओवेन" है । लुसाका सम्मेलन के प्रति पेटरिआटिक फ्रंट ने भी खुले दिल से स्वागत नहीं किया । मुगाबे एवं नकोमो का कहना था कि ब्रितानी सरकार ने मुजोरेवा शासन को वैधता प्रदान की है । साथ ही रोडेशिया संकट को अंतरराष्ट्रीय रंगमंच से हटा कर अपने हाथ में ले लिया तथा राष्ट्रसंघ एवं अफ्रीकी एकता संगठन की प्रस्तावना को अलग कर दिया । इन लोगों ने इंगलैंड के चुनाव में निरीक्षण की भूमिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि ब्रितानी सरकार को गोरे तथा मुजोरेवा प्रशासन के प्रति विशेष ख्याल है ।[87] फिर भी

86- किसिंजर कॉन्टेम्पोरारी आलयाइवस ﴾लंदन﴿ 26 अक्टूबर 1979, पृ0 29904

87- मार्टिन ग्रेगोरी - वही, पृ0 15

शक्ति अपने हाथ में लेने के लिए तैयार था । इसके द्वारा रोडेशिया के प्रति अपने वैधानिक उत्तरदायित्व तथा इस भूभाग में घटनाओं पर प्रभाव डालने की परंपरागत शक्ति की कमी के बीच की विभिन्नता को समाप्त कर रहा था । लैनकास्टर हाउस का संवैधानिक सम्मेलन एक विरोधाभास सा लग रहा था क्योंकि एक ओर ब्रितानी सरकार रोडेशिया संकट के समाधान का विश्व राजनीति में हटा कर अपना दायित्व समझ रहा था । पर इस कार्य के लिए उसे विश्व समुदाय का सहयोग आवश्यक था ।[89] इस तरीके की बुनियाद लुसाका सम्मेलन में ही शुरू हुई । लैनकास्टर हाउस में इंग्लैंड ने हरेक स्तर पर विश्व समुदाय का सहयोग लिया। पैटरिऑटिक फ्रंट ने भी रोडेशिया संकट को विश्व रंगमंच से हटाने के विरोध में विश्व समुदाय फ्रंट लाइन राज्य तथा राष्ट्रमंडल देशों की सहायता ली । लंदन का सम्मेलन ब्रिटेन तथा पैटरिआटिक फ्रंट के बीच समझौते का परिणाम था । लैनकास्टर हाउस सम्मेलन इस बात को प्रदर्शित करता रहा कि किस प्रकार हरेक प्रतिनिधि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करता है तथा इसी समर्थन से भी दूसरे पक्षों के छल-कपट के क्षेत्र को कम करता है ।[90]

संवैधानिक सम्मेलन : समस्या और परिणाम

लार्ड कैरिंगटन के नेतृत्व में सम्मेलन के 47 पूर्ण अधिवेशन हुए तथा यह 15 दिसंबर, 1979 को समाप्त हुआ । इस सम्मेलन में तीन समस्याओं पर, जो अंतःसंबंधित हैं, विचार किया गया : प्रथम, स्वतंत्र संविधान पर, दूसरे स्वतंत्रता के पूर्व का समय ।अंतरिम सरकार स्थापना तथा चुनाव

89- मार्टिन ग्रेगौरी, वही, पृ0 15

90- वही, पृ0 15

कराने तक या संक्रांति काल।, तीसरे, युद्ध विराम रेखा पर स्वीकृति।[91]

स्वतंत्र संविधान

सभी समय तक संविधान की प्रस्तावना तथा समस्या पर विचार-विमर्श किया गया। ब्रितानी प्रस्तावना ने निम्न प्रस्तावना रखी : नागरिकता, अधिकार की घोषणा, संवैधानिक राष्ट्रपति एक कार्यकारिणी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा, लोकसेवा, पुलिस सेवा, संसद जिसमें सीनेट तथा एसेंबली सभा होगी। एसेंबली सभा में अल्पमत जनों को विशेष प्रतिनिधित्व होगा। कुछ प्रस्तावनाओं पर विशेष ध्यान रखा जायेगा - जैसे संविधान में संशोधन के लिए एसेंबली सभा में 70 प्रतिशत मत की आवश्यकता तथा सीनेट के सदस्यों का दो तिहाई मत आवश्यक है।

पेटरिआटिक फ्रंट ने अपना प्रस्ताव रखा जिसमें कार्यकारी राष्ट्रपति की बात की। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान तथा सेना का प्रधान सेनापति होगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के द्वारा सीधे कार्यकारिणी कार्य करेगा। संसद में राष्ट्रपति सीनेट तथा एसेंबली सभा होगा। सीनेट का कार्य मात्र विधेयक को कुछ समय तक रोक कर रखने का हो। एसेंबली सभा में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं हो। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों का अलग अलग रूप से दो तिहाई मतों की आवश्यकता होनी चाहिए। प्रस्तावना में यह भी कहा गया कि "एकपक्षीय घोषणा" 1965 के बाद जिसे नागरिकता से वंचित कर दिया गया उसे गलत करार कर दिया जाये तथा 1970 के रोडेशिया नागरिकता कानून के अनुसार जिसे नागरिकता मिली उसे समाप्त कर दिया जाये। केवल दक्षिण रोडेशिया तथा

91- लैनकास्टर हाउस सम्मेलन के विस्तृत वर्णन के लिए देखें : "साउदर्न रोडेशिया - रिपोर्ट आफ कॉन्स्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंस" लैनकास्टर हाउस, लंदन, सितंबर-दिसंबर 1979, हर मैजेस्टी स्टेशनरी आफिस ।लंदन। पृ० 17-57.

ब्रितानी राष्ट्रीय नागरिकता कानून 1963 को सही माना जाये ।[92]

ब्रितानी प्रस्तावना तथा पेटरिऑटिक फ्रंट की प्रस्तावना के बीच काफी बड़ी खाई थी ।

19 सितंबर और 1 दिसंबर के बीच कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। लार्ड केरिंगटन ने द्विपक्षीय बातचीत की जिसमें सैलिसबरी के प्रतिनिधि ने ब्रितानी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा पेटरिऑटिक फ्रंट (पी० एफ०) ने 20 प्रतिशत स्थान गोरे के लिए संसद में आरक्षण पर राजी हो गया ।

2 अक्तूबर को पुनः बैठक शुरू हुई । नागरिकता के अधिकार पर अभी भी ब्रितानी सरकार तथा फ्रंट के बीच मतभेद रहा । ब्रितानी प्रस्ताव का कहना था कि रोडेशिया की स्वतंत्रता के पूर्व सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी जाये । पर फ्रंट का कहना था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ है उन सभी व्यक्तियों को भी स्वीकार करना जो 1965 में "एकपक्षीय घोषणा" के बाद अवैध सरकार की सहायता करता आया ।

दूसरा, जमीन अधिकार त था क्षतिपूर्ति को लेकर भी पेट्रिआटिक फ्रंट तथा ब्रितानी सरकार के बीच मतभेद था । ब्रितानी प्रस्ताव का कहना कि निजी सम्पत्ति का आवश्यक अधिग्रहण करने से रक्षा की जायेगी । अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी जल्द ही यथेष्ट क्षतिपूर्ति किसी भी देश जिम्बाब्वे के बाहर भी की जायेगी । इसके जवाब में फ्रंट का कहना था कि जिम्बाब्वे स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य जमीन को पुनः प्राप्त करना और यह जमीन जब अफ्रीकी जनता से छीनी गयी थी तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की गयी थी । अतः नयी सरकार को जनता की भलाई के लिए जमीन हासिल करने का अधिकार होना चाहिए । क्षतिपूर्ति देना सरकार का स्वनिर्णय होगा ।

92- वाइजमैन, हेनरी तथा टेलर, ए० एम०, वही, पृ० 8

11 अक्तूबर की बैठक स्थगित कर दी गयी । तथा पाँच दिनों के बाद लार्ड केरिंगटन ने घोषणा की कि यदि फ्रंट द्वारा संविधानसभा का दर्जा स्वीकार नहीं किया जाता है तो संक्रांति काल के लिए वाद-विवाद उस के बिना भी शुरू हो जायेगा । यहाँ पर ब्रितानी सरकार फ्रंट लाइन राज्य से हमेशा विचार विमर्श करती रही । फ्रंट लाइन राज्यों ने ब्रितानी प्रस्ताव मानने पर फ्रंट पर दबाव डाला । जहाँ तक जमीन की समस्या का संवेदनात्मक संबंध था, ब्रितानी एवं अमेरिकी सरकार ने कहा कि जिम्बाब्वे के कृषि विकास तथा पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता करेगा ।[93]

संक्रांति काल

22 अक्तूबर को लार्ड केरिंगटन ने संक्रांति काल के लिए ब्रितानी सरकार का 13 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया । इसमें ब्रितानी राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गयी जो कार्यकारिणी तथा विधायकी शक्ति होगा तथा राज्यपाल चुनाव आयुक्त के निरीक्षण में चुनाव करायेगा तथा राष्ट्रमंडल के देश प्रेक्षक होंगे । यह ब्रितानी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जो शर्तें लगायी गयीं उनका पालन हो । राज्यपाल सेना, पुलिस तथा नागरिक सेवा का उत्तरदायित्व लेगा। जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जायेगा वैसे ही सरकार का निर्माण किया जायेगा तथा जिम्बाब्वे स्वतंत्र हो जायेगा ।

दूसरे दिन ही फ्रंट ने ब्रितानी प्रस्ताव का खंडन किया तथा अपना अलग प्रस्ताव रखा । फ्रंट ने एक एकीकरण की बात की जिसमें फ्रंट तथा रोडेशिया शासन की सेना तथा पुलिस राष्ट्रसंघ के शांति सेना तथा

93- वाइजमैन, हेनरी तथा टेलर, ए0एम0, वही, पृ0 8-9

से सीमा पार के प्रतिबंध पर रोक तथा युद्धविराम प्रबोधकी समूह जिसमें राष्ट्रमंडल के देश भी शामिल होते, की बात की गयी ।

फ्रंट ने एक अलग प्रस्ताव भी रखा । इसमें बड़ी मात्रा में राष्ट्रसंघ की शांति सेना की उपस्थिति की मॉंग की । साथ ही फ्रंट इस बात पर राजी नहीं था कि जो क्षेत्र उसके अधीन हैं उसे सुपुर्द कर दिया जाये । उसका कहना था कि सुरक्षा परिषद की विशेष टुकड़ी बंद कर देनी चाहिए तथा उसने नागरिकों को हथियारों से वंचित कर देने की माँग की । साथ ही नागरिक पुलिस सेना की स्थापना तथा दक्षिण अफ्रीका एवं अन्य विदेशी सैनिक पदाधिकारियों को हटाने की माँग भी रखी ।

ब्रितानी सरकार इस युद्धविराम प्रस्तावना पर राजी नहीं थी ।

रोडेशिया के प्रतिनिधि ने तो ब्रितानी युद्धविराम प्रस्ताव को 26 नवंबर को स्वीकार कर लिया पर फ्रंट ने नहीं ।[95]

लार्ड केरींगटन ने पुनः 28 नवंबर को ब्रिटेन की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हरेक सेना के लिए अलग से मंडल नहीं निर्धारित किया जायेगा । साथ ही उन्होंने कहा कि दो महीना युद्धविराम के लिए लंबा समय है । उनके मत से युद्धविराम के लिए राष्ट्रमंडल के निरीक्षण आयोग की भी आवश्यकता नहीं थी । युद्धविराम आयोग तब तक काम करेगा जब तक स्वतंत्रता के बाद बहुमत सरकार की स्थापना न हो जाती ।

दो दिन के बाद फ्रंट ने सुझाया कि सुरक्षा सेना को अड्डों से हटा लेना चाहिए तब फ्रंट की सेना भी कंपनी स्तर तक इकट्ठा हो जायेगी । फ्रंट ने फिर कहा कि रोडेशियन वायुसेना को भूमि पर उतारना जरूरी है। फ्रंट चाहता था कि राष्ट्रमंडल युद्धविराम प्रबोधकी सेना को बढ़ा दिया जाये जिसमें नाइजीरिया, भारत, घाना, सीरिया, सीओने, गुआइना तथा जमैका सम्मिलित हों तथा इसे राष्ट्रमंडल के महासचिव तथा राज्यपाल को रिपोर्ट करे ।[95]

95- वाइज मैन, हेनरी, तथा टेलर, ए० एम० वही, पृ० 12

लार्ड केरिंगटन ने फ्रंट के नेता मुगाबे तथा नकोमो से आग्रह किया कि वे अपने युद्धविराम प्रस्ताव पर फिर से विचार करें तथा ब्रितानी प्रस्ताव को (कुछ संशोधन के बाद) स्वीकार करें । 5सितंबर को फ्रंट ने ब्रितानी प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा दूसरे दिन इस बात पर वाद-विवाद शुरू हुआ कि युद्धविराम को कैसे लागू किया जाये । अंततः सभी पक्ष इसके लिए राजी हो गये ।

फ्रंट के नेताओं को फ्रंट लाइन राज्यों के दबाव के कारण ब्रितानी योजना -- स्वतंत्र संविधान संक्रांति काल तथा युद्धविराम संधि-- को स्वीकार करना पड़ा । उन्होंने काफी रियायत दीं :

1- शुरू में फ्रंट ने कार्यकारिणी राष्ट्रपति की मांग की थी पर अंत में उसे संवैधानिक राष्ट्रपति पर राजी होना पड़ा ।

2- अफ्रीकी नेताओं ने मांग की कि गोरों के लिए मात्र 3 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होना चाहिए पर अंत में उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण पर राजी होना पड़ा ।

3- शुरू में मांग की कि चाहे अफ्रीकी हो या गोरे सभी के लिए एक ही मतदाता व नामावली हो पर अंत में उसे रंगभेद प्रणाली स्वीकार करनी पड़ी जिसमें अफ्रीकी तथा गोरों के लिए अलग-अलग मतदान की व्यवस्था थी ।

4- शुरू में जमीन के अधिकार तथा क्षतिपूर्ति के तरीके का कड़ा विरोध किया गया था पर अंत में गोरों पर्याप्त क्षतिपूर्ति पर राजी हो गया ।

5- शुरू में छह महीने के संक्रांतिकाल की मांग रखी गयी थी पर अंत में युद्धविराम के बाद से चुनाव तक दो महीने पर ही सहमति हो गयी ।

6- अफ्रीकी नेताओं की मांग थी कि राष्ट्रसंघ की सेना रोडेशिया में संक्रांतिकाल में आदेशों का पालन करने के लिए होनी चाहिए पर

अंत में इस कार्य के लिए राष्ट्रमंडल की सेना पर सहमति हुई ।

7- शुरू में फ्रंट की मांग थी कि उसके छापामार सैनिकों के लिए एकत्र होने की जगह रोडेशियन सेना के बराबर होनी चाहिए पर अंत में वह राजी हो गया कि टुकड़ियां 16 जगहों पर एकत्र होंगी जो कि रोडेशिया सेना के एकत्र होने की जगहों की संख्या का आधा थी ।

8- फ्रंट ने वायुसेना को भूमि पर उतरने की बात कही पर अंत में इस बात पर राजी होना पड़ा कि वायुसेना राज्यपाल के निरीक्षण में रहेगी ।

इस प्रकार देखा जाये तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें फ्रंट के नेताओं को न चाह कर भी स्वीकार करना पड़ा । ब्रितानी प्रस्ताव पर राजी होने के लिए मोर्चे पर फ्रंट लाइन राज्यों द्वारा काफी दबाव डाला गया व प्रेत्साहन का काफी प्रयोग हुआ ।[96]

लार्ड साम्स 6 दिसंबर को रोडेशिया का राज्यपाल नियुक्त किया गया । इनका काम लैंकास्टर हाउस सम्मेलन के निर्णय को लागू करना था । ब्रितानी सरकार का रोडेशिया पर वैध अधिकार हो गया तथा आर्थिक अवपीड़न (या प्रतिबंध) को हटा लिया गया । 18 दिसंबर, 1979 को रोडेशिया से संबंधित विधेयक पर ब्रितानी राजशाही सहमति मिल गयी । तीन दिन के बाद एक समारोह में लैंकास्टर हाउस सम्मेलन के निर्णयों पर अध्यक्ष लार्ड ड्रिंग्ली सील, मुजोरेवा, डा० मुंडावारारा (रोडेशियन सरकार का प्रतिनिधि) तथा नकोमो एवं मुगाबे के बीच हस्ताक्षर हुए ।

96- लीमेरो, टिलडेन जे० - "विनिंग अगेंस्ट ए स्टेक्ड डेक्स : दी इलेक्शन इन जिम्बाब्वे", अफ्रीका टुडे (लंदन) वाल्युम 27, नं० 1, 1980, पृ० 10

लेनकास्टर हाउस सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार गोरों के लिए चुनाव 14 फरवरी तथा अफ्रीकीयों के लिए 27-29 जनवरी को हुआ। पश्चिमी जगत को आशा थी कि इस चुनाव में कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं ले पायेगा। फलतः मुजोबा अन्य दल के नेता के साथ मिल कर सरकार बनाने में समर्थ हो जायेगा। यह आशा के विपरीत हुआ। चुनाव में पेट्रियाटिक फ्रंट विजयी हुआ। फ्रंट के सत्ता में आने पर यह कहा गया कि चुनाव में बहुत धाँधलेबाजी हुई। यह चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं था। पर भारत के रामेश्वर दयाल के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल प्रेक्षक समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, "हम लोग चुनाव के संचालन की सत्यनिष्ठा से पूर्ण संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि भले टिका की सुरक्षा एवं मतगणना की विशुद्धता पर भी हम लोग संतुष्ट हैं।"[97]

97- कॉमनवेल्थ करेंट्स (लंदन), अप्रैल 1980, पृ0 3

अध्याय : 4

निष्कर्ष

समसामयिक राजनय में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवपीड़न एवं प्रत्यायन का प्रयोग सामान्य रूप से होता है । अवपीड़न का मुख्य उद्देश्य है कि अपने को बिना हानि पहुँचाये दूसरे पक्ष को वांछित समझौते के लिए बाध्य करना । अवपीड़न का प्रयोग सैनिक या आर्थिक प्रतिबंध के रूप में होता है । समसामयिक राजनय में आर्थिक अवपीड़न का प्रयोग काफी प्रचलित है । इसमें दूसरे पक्ष को "उत्तर देने का" उचित समय मिल जाता है । अगर आर्थिक अवपीड़न का प्रयोग सही ढंग से किया जाये तो यह सैनिक बलप्रयोग से ज्यादा कारगर साबित होता है । अवपीड़न का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किया जाता है । सामूहिक या व्यक्तिगत अवपीड़न का प्रयोग समस्या के आकार प्रकार पर निर्भर करता है । अगर किसी समस्या से पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को खतरा है तो अवपीड़न का स्वरूप सामान्य एवं सर्वव्यापक हो जाता है । और अगर किसी क्षेत्र विशेष की समस्या हो तो क्षेत्र विशेष के देश ही भाग लेते हैं । अवपीड़न का सही प्रयोग तभी माना जाता है जब पीड़ित पक्ष प्रयोग करने वाले के अनुसार अनुपालन करने के लिए तैयार हो । अवपीड़न के उल्लंघन की बहुत संभावना रहती है, विशेषकर आर्थिक अवपीड़न में ।

प्रत्यायन का प्रयोग भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आम बात है । इसका भी वही उद्देश्य है -- किसी खास उद्देश्य की पूर्ति करना । इसका प्रयोग एकाएक नहीं होता । इसके द्वारा धीरे-धीरे, क्रिया - प्रतिक्रिया, वाद-विवाद, परामर्श आदि द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है । इसमें कई अभिनेता भाग लेते हैं । मुख्यतः अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देश भाग लेता है । साथ ही संगठन विशेष जैसे- राष्ट्रसंघ, राष्ट्रमंडल, अफ्रीकी एकता संगठन, फ्रंट लाइन राज्य आदि

भाग लेते हैं ताकि समस्या का समाधान प्रत्यायन द्वारा न्यायोचित ढंग से हो सके । प्रत्यायन द्वारा समस्या के समाधान में लंबा समय लगता है पर यह स्थाई होता है तथा सभी पक्षों को अपना पक्ष स्पष्ट करने का उचित मौका मिलता है । विचार-विमर्श, वाद-विवाद आदि के द्वारा किसी बात निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है जिससे सभी पक्ष संतुष्ट रहते हैं ।

जिम्बाब्वे के संकट में अपीड़न तथा प्रत्यायन का प्रयोग इन दो राजनयिक प्रक्रियाओं उपकरणों के समायोजन का एक अच्छा उदाहरण है । इस संकट में अपीड़न एवं प्रत्यायन का प्रयोग काफी लंबे समय तक हुआ । स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिम्बाब्वे का संघर्ष एक अजीब उदाहरण है । सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि किसी उपनिवेश के मूलवासी अपनी स्वतंत्रता को औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध लड़ कर प्राप्त करता है । पर जिम्बाब्वे में अफ्रीकावासियों को दो औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ना पड़ा । एक तो ब्रितानी सरकार से जो वैधानिक रूप से उपनिवेश की मालिक थी-- दूसरे, रोडेशिया में ही बसे अल्पमत गोरों से जो रोडेशिया जाकर बस गये थे तथा वहाँ की प्राकृतिक सम्पदा तथा अफ्रीकी जनता का शोषण अपने हितों के लिए कर रहे थे । 11नवंबर 1965 को अल्पमत श्वेतवासियों ने "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" कर ब्रिटेन से सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सैनिक आदि संबंधों को तोड़ दिया । अफ्रीकी अपने आत्मनिर्णय के लिए "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" के बाद 15 वर्षों तक लड़ते रहे । इतना ही नहीं बल्कि अफ्रीका-वासी को अन्य साम्राज्यवादी ताकतों जैसे- अमेरिका, पुर्तगाल, द० अफ्रीका आदि देशों से भी मुकाबला करनापड़ा ।

साम्राज्यवादी ताकतों ने अपनी स्वार्थलोलुपता तथा छलकपट को यह कह कर न्यायसंगत बताया कि अफ्रीकावासी को "सभ्य तथा शिक्षित" करने का काम मात्र यूरोपियनों का है । अफ्रीका वासी को जंगली एवं असभ्य करार कर दिया । 1884-85 में जब बर्लिन सम्मेलन हुआ तभी इस

सिद्धांत को खूब प्रोत्साहन दिया गया । आर्थिक संपदा की लूट में ब्रिटेन सबसे आगे रहा । इस क्षेत्र में सीसिल रोड की "ब्रितानी दक्षिण अफ्रीका - कंपनी" को व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया । इससे ब्रितानी सरकार को भी फायदा होता रहा । सरकार से प्रोत्साहन पाकर श्वेतवासी वहाँ बसते गये । समय के अंतराल में श्वेतवासी अपने राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों की माँगों को बढ़ाते चले गये । 1922 में श्वेतवासी ने रोडेशिया को दक्षिण अफ्रीका का पाँचवाँ प्रांत बनाने के विरुद्ध जनमत व्यक्त किया । 1923 में रोडेशिया में कंपनी शासन समाप्त हो गया तथा वहाँ के श्वेतवासियों को उत्तरदायी सरकार प्रदान की गयी । जब उत्तरी रोडेशिया में ताँबे की खान का पता चला तो दक्षिणी रोडेशिया के वासी उत्तरी तथा दक्षिण रोडेशिया की एकता की माँग करने लगे । फलतः 1953 में दक्षिणी, उत्तरी तथा मध्य रोडेशिया को मिलाकर एक "संघ शासन" कायम कर दिया । पर यह संघ शासन श्वेतवासियों के रंगभेद नीति एवं अफ्रीकी आंदोलन के कारण 1961 के करीब भंग हो गया ।

अब श्वेतवासी द0 रोडेशिया की स्वतंत्रता की माँग करने लगे । साथ ही श्वेतवासियों ने द0 रोडेशिया के लिए नये संविधान को भी प्रस्तुत किया जिसका मुख्य उद्देश्य था- इंगलैंड को दक्षिणी रोडेशिया के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कम करना, दूसरे अफ्रीकी जनता को आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना, तीसरे, श्वेतवासियों की सम्प्रभुता को कायम रखना । अब श्वेतवासी "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" का भी आभास ब्रितानी सरकार को देने लगा । लेबर पार्टी की बातचीत से भी समाधान न निकल सका और अंततः 11 नवंबर 1965 को इआन स्मिथ ने "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" भी कर दी ।

स्मिथ की एकपक्षीय कार्रवाई के प्रतिकार में ब्रितानी सरकार कुछ भी नहीं कर सकी । यह बात जरूर है कि लेबर सरकार ने इस कार्रवाई को अवैध घोषित कर दिया । पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया । प्रधानमंत्री

विल्सन ने कहा कि यह स्मिथ की सरकार मात्र तीन-चार दिन की बात है । पर यह तीन-चार दिन तक कायम न रह कर 15 वर्षों तक कायम रही । विश्व समुदाय विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के वासियों ने स्मिथ के विरुद्ध इंगलैंड से सैनिक कार्रवाई की माँग की । पर ब्रिटेन सैनिक अवरोध के स्थान पर आर्थिक अवरोध पर निर्भर था । और खेद की बात यह है कि आर्थिक अवरोध का प्रयोग भी सही अर्थों में नहीं हुआ। शुरू में सीमित आर्थिक प्रतिबंध लगाया फिर बाद में आदेशात्मक तथा अंत में सर्वव्यापक प्रतिबंध लगाया गया ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या ब्रितानी सरकार-- चाहे अनुदार दल की सरकार हो या लेबर पार्टी की-- ने सही अर्थों में आर्थिक अवरोध का प्रयोग किया ? क्या ब्रितानी सरकार सच्चे अर्थों में अफ्रीकी सरकार या बहुमत शासन लाना चाहती थी ? अगर हाँ, तो ब्रितानी सरकार ने इसके लिए क्या नीति अपनायी तथा क्या प्रयास किया ?

अगर ब्रितानी सरकार की नीति एवं रणनीति की सही छानबीन एवं जाँच की जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इंगलैंड कभी भी यह नहीं चाहता था कि द0 रोडेशिया में अफ्रीकी शासन कायम हो । अगर देखें तो पता चलता है कि इंगलैंड को श्वेत अल्पमत के प्रति विशेष अनुराग था । इंगलैंड हमेशा ही अल्पमत श्वेतवासी के राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक माँगों को पूरा करते रहे चाहे 1923 की उत्तरदायी सरकार हो या 1953 में "संघ शासन" की घोषणा करना । यहाँ तक कि जब "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" इआन स्मिथ ने कर दी तब भी इंगलैंड ने सैनिक अवरोध के विरुद्ध रहा । वह आर्थिक अवरोध पर निर्भर रहा जिसमें उल्लंघन के सभी द्वार खुले छोड़ दिये गये । पेट्रोल, जो रोडेशिया की अर्थव्यवस्था के लिए प्राणाधार था, बहुत दिनों तक आर्थिक प्रतिबंध से अलग रखा गया । यह सच है कि अंत में सामान्य एवं सर्वव्यापक आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की गयी । पर इसके बाद भी इंगलैंड रोडेशिया में

बहुमत शासन लाने में असमर्थ रहा । इसके कई कारण थे :

प्रथम, आर्थिक प्रतिबंध धीरे-धीरे लगाया गया । इस आर्थिक अवपीड़न में सभी देशों ने भाग नहीं लिया । पुर्तगाल तथा द०अफ्रीका खुले रूप से रोडेशिया श्वेतवासियों को आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक रूप से सहायता करते रहे । रोडेशिया का आयात-निर्यात इन देशों से तो होता ही था- साथ ही इन देशों के द्वारा विश्व के अन्य देशों से भी आयात निर्यात होता है । द० अफ्रीका तथा पुर्तगाल सरकार के आयात-निर्यात आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि रोडेशिया का व्यापार इन्हीं देशों के द्वारा हुआ । यह सही है कि रोडेशिया का आयात-निर्यात घटा तो जरूर पर साथ ही द० अफ्रीका एवं पुर्तगाल सरकार का एकाएक बढ़ गया ।

दूसरे, आर्थिक अवपीड़न का उल्लंघन यूरोप की निजी कंपनियों द्वारा काफी हुआ । कैलटेक्स, मोबिल, टोटल तथा बी०पी० तेल कंपनियों को तेल के उल्लंघन में पकड़ा गया जिसकी पुष्टि ब्रितानी सरकार द्वारा भी की गयी । तीन बोईंग जेटों का रोडेशिया सरकार को निर्यात भी आर्थिक अवपीड़न का उल्लंघन ही था ।

तीसरे, स्विटजरलैंड ने आर्थिक अवपीड़न के लागू करने से सीधा इनकार कर दिया । स्विटजरलैंड का सोचना था कि प्रतिबंध को लागू करने से उसकी वर्षों से चली आ रही "तटस्थता की नीति" को धक्का पहुँचेगा अतः उसने प्रतिबंध में भाग नहीं लिया ।

चौथे, महाशक्ति अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध में भाग नहीं लिया । यों शुरू में तो भाग लिया पर 1971 में "बायर्ड संशोधन" के द्वारा अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध से मुक्त हो गया ।। अमेरिका सैनिक मामलों से संबंधित प्राकृतिक खनिज जैसे क्रोम, निकल, आस्बेस्टस आदि का आयात अब खुले आम रोडेशिया से करने लगा । क्रोम का उत्पादन सोवियत संघ के बाद रोडेशिया में ही बड़े पैमाने पर होता है । अतः सोवियत संघ से अच्छे संबंध न होने तथा इस पर ज्यादा निर्भर न रहने

के उद्देश्य से "बायर्ड संशोधन" करना ही उचित समझा ।

ऐसी स्थिति में इंग्लैंड ने आर्थिक अवपीड़न को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की । अंततः ब्रितानी सरकार ने भी प्रत्यायन का सहारा समस्या-समाधान के लिए लिया । इससे द्वारा भी गोरे शासन को ही वैधता प्रदान करने की कोशिश की । यह एक "विरोधाभास" है कि इंग्लैंड द० रोडेशिया में बहुमत शासन की बात की पर शुरू में जो भी बातचीत हुई-- चाहे टाइगर बातचीत हो या फीयरलेस बातचीत-- किसी में भी अफ्रीकावासियों को शामिल नहीं किया गया । इंग्लैंड में सरकार-- चाहे अनुदार दल की हो या लेबर दल की-- किसी ने भी सच्चे अर्थों में समस्या का समाधान कभी नहीं चाहा । लेबर पार्टी के समय में ही "स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा" की गयी । अनुदार दल तो एक कदम और आगे था । 1971 में जब वह सत्ता में आया तो बिना अफ्रीकी जनता के उचित समर्थन के अल्पमत श्वेतवासी के साथ संधि कर ली ।

1974-75 में अफ्रीकी रंगमंच पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिन्होंने रोडेशिया के इतिहास में एक नया मोड़ दिया । इस समय अंगोला, मोजाँबीक, जो पुर्तगाल के उपनिवेश थे, स्वतंत्र हो गये । अंगोला एवं मोजाँबीक का स्वतंत्र होना न केवल रोडेशिया के लिए महत्व रखता है बल्कि परिणामतः अमेरिका, जो वर्षों से रोडेशिया की समस्या से अलग था, उसे भी विवाद में शामिल होना पड़ा । अमेरिका दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं को अब अपने विश्व रणनीति के अनुसार मापने लगा । अमेरिका का मानना था कि अंगोला एवं मोजाँबीक की स्वतंत्रता में सोवियत संघ एवं क्यूबा का हाथ है । साम्यवाद के विस्तार के आतंक (दक्षिण अफ्रीका में) हेनरी किसिंजर एवं निक्सन को नजर आने लगा और वे सोचने लगे कि इससे अमेरिकी हितों का खतरा पड़ सकता है । अतः किसिंजर अपने शटल राजनय के साथ रोडेशिया की समस्या में कूद पड़े । "साम्यवाद का विस्तार" किसिंजर की मात्र मनगढ़ंत कथा थी ।

साम्यवाद के विस्तार के नाम पर अमेरिका अपनी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नीतियों को पूरा करना चाहताथा । आर्थिक लाभ एवं सैनिक नीति उसका दीर्घकालीन उद्देश्य थे । यह बात "बायर्ड संशोधन" से भली भाँति पता चल जाती है । अमेरिका के पास बहुतायत रूप में क्रोम था । सैनिक उपयोग के बाद बचा क्रोम नागरिक उपयोग के लिए बाँटा तक गया था । इसके बाद भी आर्थिक प्रतिबंध का उल्लंघन कर क्रोम का आयात करने लगा । सोवियत संघ के बहाने अमेरिका वहाँ खुद उपस्थित रहना चाहता था । अमेरिका का अल्पकालीन उद्देश्य था कि रोडेशिया में एक ऐसे शासन की स्थापना की जाये जो अमेरिका तथा यूरोपीय नीतियों का समर्थन करे । यदि बहुमत का शासन भी स्थापित हो जाये तो बेहतर था क्योंकि बढ़ते विश्व जनमत के कारण रोडेशिया में बहुमत शासन अवश्यंभावी नजर आ रहा था ।

रोडेशिया के संकट में अपपीड़न तथा प्रत्यायन का प्रचुर प्रयोग हुआ। अगर यह कहा जाये कि अपपीड़न एवं प्रत्यायन के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया गया तो अतिशयोक्ति न होगी । वस्तुतः राजनय का उद्देश्य भी यही है कि दो विरोधी हितों का समायोजन करना । अनुनय-विनय, प्रत्यायन, सौदेबाजी आदि राजनय के सार तत्व हैं ।

रोडेशिया के संकट में यह कहना गलत होगा कि एक खास समय में केवल अपपीड़न या प्रत्यायन मात्र का प्रयोग हुआ । वस्तुतः प्रत्यायन का प्रयोग 1965 के स्मिथ की एकपक्षीय घोषणा के पूर्व से ही शुरू हुआ । पर इसके बाद प्रत्यायन मुख्य न रह कर अपपीड़न मुख्य हो गया । जब किसिंजर सोवियत संघ तथा क्यूबा के नाम पर दक्षिण अफ्रीका के रंगमंच पर आया तब प्रत्यायन का काल स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गया और तब भी राष्ट्रवादी नेताओं को भी हरेक संधिवार्ता में शामिल किया जाने लगा । चाहे वह जेनेवा सम्मेलन हो या लुसाका का या लेनकास्टर हाउस का । शुरू में अफ्रीकीयाती का जब भाग्य निर्धारण

होता था तब अफ्रीकी जनता को शामिल न कर अवैध सरकार तथा ब्रितानी सरकार के बीच बातचीत होती थी । पर 1974-75 के बाद संधिवार्ता का क्षेत्र एवं स्वरूप बदल गया । इसमें भाग लेने वाले अभिनेता भी बदल गये । फलतः प्रत्यायन का क्षेत्र भी बदल गया और ऐसा नजर आने लगा कि समस्या का समाधान हो सकता है ।

जिम्बाब्वे संकट के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका तथा इंगलैंड की रणनीति के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग अवपीड़न का प्रयोग सही अर्थों में नहीं कर रहे थे, फलतः समस्या और अधिक समय तक बनी रही । प्रत्यायन के प्रयोग में अमेरिकी तथा ब्रितानी सरकार ने "दबाव के दाँवपेंच" का प्रयोग किया । 1976 में इआन स्मिथ ने किसिंजर योजना को द0 अफ्रीका के दबाव से ही स्वीकार किया । दूसरी ओर अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेता पर फ्रंट लाइन राज्य विशेषकर जाँबिया तथा मोजांबीक का दबाव आ रहा था । ब्रितानी सरकार ने भी"फ्रंट लाइन" के द्वारा ही अफ्रीकी राष्ट्रवाद पर "दबाव के दाँवपेंच" का ही प्रयोग किया । लैनकास्टर हाउस सम्मेलन में यह रणनीति बिल्कुल स्पष्ट हो गयी । जब भी अफ्रीकी नेताओं-- चाहे स्वतंत्र संविधान के प्रस्ताव हों या संक्रांति काल का युद्धविराम का प्रस्ताव हो-- अपना अलग प्रस्ताव रखा, उस पर फ्रंट लाइन का दबाव आया कि वह ब्रितानी प्रस्ताव को स्वीकार करे तथा कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे ।

रोडेशिया संकट के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेता आपस में लड़ते रहे थे । यह लड़ाई छोटी-छोटी बातों को लेकर होती थी जिसके कारण बड़े उद्देश्य की पूर्ति में लंबा समय लग रहा था । यह सही है कि सभी एकमत थे कि बहुमत का शासन हो पर इसे प्राप्त करने के लिए आपसी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने में असमर्थ पा रहे थे । अफ्रीकी नेताओं में यह होड़ थी कि कौन सबसे पहले

अफ्रीकी प्रधानमंत्री बनता है। इस स्वार्थ को पूरा करने में अफ्रीकी राष्ट्रवादी अपने मुख्य उद्देश्य--- बहुमत का शासन--- से भी विचलित हो जाते थे। नकोमो ने भी स्मिथ के साथ कई बार बातचीत की। बिशप मुजोवा ने तो 1978 में स्मिथ के साथ बिना अफ्रीकी जनता का ख्याल रखे आंतरिक समझौता भी कर लिया। इस समझौते के कारण गोरों की सम्प्रभुता बनी रही। देखने में तो लगता था कि बहुमत शासन है पर सभी अधिकार गोरों के हाथ में थे। बहुमत का शासन छलावा मात्र था। विश्व के जनमत ने इस आंतरिक समझौते का डट कर विरोध किया। इस प्रकार यह आपसी कलह भी समस्या को हल करने में बाधा पहुंचाई। इससे न केवल अल्पमत श्वेत शासन को एक बहाना मिला बल्कि अमेरिका तथा ब्रिटेन को भी अपने मन के मुताबिक कार्य करने में आसानी थी। अंततः बहुसंख्यक अश्वेतों को स्वतंत्रता मिली पर अथपीड़न एवं प्रत्यायन के बिना नहीं।

संदर्भ सूची

प्राथमिक स्रोत

1- "एटेम्पट एट ए पीसफुल सेटलमेंट इन साउदर्न रोडेशिया"
(पेपर प्रिपेयर्ड बाय यू0 एन0 सिक्रेटेरियेट)
आब्जेक्टिव : जस्टिस (ए क्वार्टर मैगजीन आफ यू0एन0 ओ0)
वाल्यूम-9, नं0-1, स्प्रिंग 1977

2- "एन एनालीसीस आफ दी इलीगल रिजीम्स कांस्टीट्यूशन फार जिम्बाब्वे रोडेशिया"
आब्जेक्टिव : जस्टिस (ए क्वार्टर मैगजीन आफ यू0एन0ओ0)
वाल्यूम-11, नं0 1, 2, स्प्रिंग, 1979

3- अफ्रीका रिकॉर्ड , मार्च-अप्रैल 1976, वाल्यूम-18, नं0 7

4- अफ्रीका डायरी (नयी दिल्ली)
9 अप्रैल, 1974
25 जुलाई, 1974

5- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन (लंदन)
"इकानामिक फिनान्शियल एंड टेक्नीकल सीरीज"
फरवरी 15- मार्च 14, 1973
अप्रैल 15 मई 14, 1973

6- अफ्रीका रिसर्च बुलेटिन (अफ्रीका रिसर्च लि0, लंदन)
नवंबर 1-30, 1965, दिसंबर 1-31, 1965, जनवरी 1-31-1966
मार्च 1-31, 1966, अप्रैल 1-30, 1966, मई 1-31, 1966,
जून 1-30, 1966, दिसंबर 1-31, 1966, सितंबर 1-30, 1967
अक्तूबर, 1-31, 1968, दिसंबर 1-31, 1968

7- कीसिंग्स कंटेम्पोरारी आरकाइव्स (लांगमेन ग्रुप लि0, लंदन)
फरवरी 9, 1979

8- कीसिंग्स कानटेम्पोरारी आरकाइव्स, ।लॉंगमैन ग्रुप लि0, लंदन।
वाल्यूम 25, अगस्त 1979

9- "रोडेशिया : प्रोपोजल फार ए सेटलमेंट"
आब्जेक्टिव : जस्टिस ।ए क्वाटर मैगजीन आफ यू0एन0ओ0।
वाल्यूम 9, नं0 3, आटम 1977

10-"रीसेंट डेवलपमेंट इन साउदर्न रोडेशिया" ।पेपर प्रिपेयर्ड बाय
यू0 एन0 सेक्रेटेरियट। आब्जेक्टिव : जस्टिस । क्वाटर मैगजीन
आफ यू0एन0ओ0।
वाल्यूम 8, नं 1, स्प्रिंग 1976

11-साउदर्न रोडेशिया : रिपोर्ट आफ दी कांस्टीट्युशन कानफेरेंस,
लैंकास्टर हाउस, लंदन, सितंबर-दिसंबर 1979
हर मैजेस्टी स्टेशनरी आफिस ।लंदन। कमांड 7802

12- सलीम ए0 सलीम - "दी इंटरनल सेटलमेंट इन रोडेशिया"
आब्जेक्टिव : जस्टिस ।ए क्वाटर मैगजीन आफ यू0 एन0 ओ0।
वाल्यूम- 10, नं0 1 स्प्रिंग-1978

13- "स्ट्रगल एंड रीप्रेशन इन साउदर्न रोडेशिया"
।पेपर प्रिपेयर्ड बाय यू0एन0 सेक्रेटेरियट।
आब्जेक्टिव : जस्टिस ।ए क्वाटर मैगजीन आफ यू0एन0ओ0।
वाल्यूम 6, नं0 2 अप्रैल, मई, जून- 1974

14-"सेक्शन एंड दी साउदर्न रोडेशिया इकानामी"
।रिपोर्ट आफ दी स्पेशल कमेटी टू दि करेंट जेनरल एसेंबली।
आब्जेक्टिव्स : जस्टिस ।ए क्वाटर मैगजीन आफ यू0एन0ओ0।
वाल्यूम 6, न0 4, अक्तूबर-नवंबर-दिसंबर 1974

15- सीसे, जीने मार्टिन - "इम्पलीमेंटिंग सैंक्शन अगेंस्ट साउदर्न रोडेशिया"
आब्जेक्टिव : जस्टिस ।एक्वाटर मैगजीन आफ यू0एन0ओ0।,
वाल्यूम 6, नं0 1, जनवरी-फरवरी-मार्च , 1974

16- "दी साउदर्न रोडेशिया सेटलमेंट प्रोपोजल्स इसाय दे वर रिजेक्टेड"
(दी रिपोर्ट आफ पीयर्स कमीशन आन रोडेशिया)
आब्जेक्टिव : जस्टिस (ए क्वाटर मैगजीन आफ यू० एन० ओ०)
वाल्यूम 4, नं० 4, 1972

17- प्रो० ग्रेरचाली, सी०एन - "इन साउदर्न रोडेशिया:ए प्राइसीस आफ दी न्यो कोलोनियल सिस्टम"
आब्जेक्टिव : जस्टिस (ए क्वाटर मैगजीन आफ यू०एन०ओ० कावेरिंग दी यू एन० एक्टिविटी अगेंस्ट एपारथेड, रेशियल डिस्क्रीमिनेशन एंड कोलोनियलिज्म)
वाल्यूम-4, नं० 3, 1972

किताबें :

1- हटसन, एच०पी०डब्ल्यू०-- "रोडेशिया - इंडींग एन एरा"
हेरीटेज पब्लिशर्स (नयी दिल्ली), 1979

2- जार्ज शेपर्डर एम० - (एडीटेड)
"मैनेजिंग यू० एस० -सोवियत राइवलरी
प्राब्लम आफ काइसीस प्रीमेंशन"
वेस्टव्यू प्रेस (यू० एस० ए०), 1983

3- कार्टर ग्वेनडोलेन एम० एंड ओमेरा, पेट्रिक (एडीटेड)
"इंटरनेशनल पालिटिक्स इन साउदर्न अफ्रीका"
इंडियाना यूनीवर्सिटी प्रेस (यू०एस०ए०) 1982

4- ओमेरा पेट्रिक - "रोडेशिया : रेशियल कान्फ्लिक्ट और कोइग्जीसटेंस?"
कोरनेल यूनीवर्सिटी प्रेस (इथाका), 1975

5- मार्टिन, डेविड एंड जॉनसन, फिलिप - "दी स्ट्रगल फार जिम्बाब्वे दी चिमुरेंगा वार"
फाबेर एंड फाबेर लिमिटेड (लंदन) 1981

6- प्राइस रोबर्ट एम० - "यू० एस० पालिसी टुवर्ड्स साउदर्न अफ्रीका-इंटरेस्ट, च्वाइसेज एंड कॉन्स्टरेंस"
कार्टर, जी०एम० एंड ओमेर पी० (एडीटेड)-
"इंटरनेशनल पालिटिक्स इन साउदर्न अफ्रीका"
इंडियाना यूनीवर्सिटी प्रेस (यू० एस० ए०) 1982

7- सीगेर, जॉन ।एडीटेड। - "साउदर्न अफ्रीका सीन्स दी पुर्तगीज कू"
वेस्ट व्यू प्रेस ।यू०एस०ए०। 1980

8- सीमसॉन, हावार्ड - "रिसर्च रिपोर्ट नं0 53
जिम्बाब्वे ए कंट्री स्टडी"
दी स्कैंडनेवियन इंस्टीट्यूट आफ अफ्रीकन स्टडीज ।स्टाकहोम। 1979

9- म्लाम्बो,इस्माइल - "रोडेसिया दी स्ट्रगल फार ए बर्थराइट"
सी0 हर्स्ट एंड कंपनी पब्लिशर्स लि0 ।लंदन। 1972

10- विंडरीच, एलन- "ब्रिटेन एंड दी पालिटिक्स आफ रोडेसिया इंडीपेंडेंट"
क्रूम हेल्म लि0 ।लंदन।, 1978

11- विंडरीच, एलन - "दी रोडेसिया प्राब्लम ए डोकोमेंटरी रिकार्ड 1923-1973",
राउटलेज एंड केगन पॉल लि0 ।लंदन।, 1975

12- वाइजमेन, हेनरी तथा टेलर, एलोस्टे यर एम0
फ्राम रोडेसिया टु जिम्बाब्वे : दी पालिटिक्स आफ ट्रान्जीशन
परगामॉन प्रेस ।न्यूयार्क, आक्सफोर्ड।, 1981

13- यंग कीनिथ - "रोडेसिया एंड इंडीपेंडेंट : ए स्टडी इन ब्रिटिश कोलोनियल पालिसी"
इयरे एंड स्पॉटीसवुड ।पब्लिशर्स। लि0 ।लुंदन।, 1967

लेख

1- बेल्फिग्लियो, वेलेन्टाइन जे --- "ए केस फार रोडेसिया"
अफ्रीकन एफेयर्स ।आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस। लंदन
वाल्यूम 77, नं0 307, अप्रैल 1978

2- छाबड़ा, हरिचरण - "आइल टू रोडेसिया- ए वेस्टर्न कान्सिपिरैसी"
इंडिया क्वाटरली ।नयी दिल्ली।, जनवरी-मार्च, 1978

3- डे, जॉन - रोडेसियन स्ट्रेटेजी
दी राउंड टेबल ।लंदन। नं0 226,अप्रैल 1977

4- डे, जॉन, "दी रोडेसियन इंटरनल सेटलमेंट"
दी वर्ल्ड टुडे ।लंदन। जुलाई 1978

5- डे, जॉन - "दी डिवीजन आफ दी रोडेशियन अफ्रीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट"
दी वर्ल्ड टुडे ।लंदन।, वाल्यूम 23, नं0 10, अक्तूबर 1977

6- इन्ग्राम, डेरेक - "लुसाका 1979 : ए सीग्नीफिकेंट कामनवेल्थ मीटिंग"
दी राउंड टेबल, ।लंदन।, नं0 276, अक्तूबर 1979

7- इन्ग्राम, डेरेक - "इफ रोडेशिया क्रम्बल्स"
दी राउंड टेबल ।लंदन।, नं0 256, अक्तूबर 1974

8- ग्रेगोरी, मार्टिन - "रोडेशिया : फ्राम लुसाका टू लैनकास्टर हाउस"
दी वर्ल्ड टुडे ।लंदन।
वाल्यूम 30, नं0 1, जनवरी 1980

9- गाल्तुंग, जॉन- "आन दी इफेक्ट आफ इंटरनेशनल इकानामिक सैक्शन विद एक्जाम्पल फ्राम दी केस आफ रोडेशिया"
वर्ल्ड पालिटिक्स ।प्रिंसटन यूनीवर्सिटी प्रेस। यू0 एस0 ए0
नं0 3, अप्रैल 1967

10- गन, एल0 एच0 - "प्रोस्पेक्ट फार ह्वाइट सैटीलर्टस"
अफ्रीका रिपोर्ट ।यू0 एस0ए0।
वाल्यूम नं0 22, नं0 5, सितंबर-अक्तूबर 1977

11- लिवी, रोनाल्ड टी0 - "एंग्लो-अमेरिकन डिप्लोमैसी एंड रोडेशियन सैटलमेंट! ए लॉस आफ इम्पेटुस"
आरबिस ।ए जर्नल आफ वर्ल्ड एफेयर्स। यू0 एस0 ए0
वाल्यूम 23, नं0 1, स्प्रिंग 1979

12- लीमीली, टिलडेन जे0 - "विनिंग अगेंस्ट ए स्टैक्ड डेक : दी एलेक्शन इन जिम्बाब्वे"
अफ्रीका टुडे ।यूनीवर्सिटी आफ डेनवर कोलोराडो। यू0 एस0 ए0
वाल्यू 23, नं0 1, फर्स्ट क्वाटर 1980

13- मुरापा, रुकुदजो - "दी जिम्बाब्वे क्राइसीस : एन एनालीसीस आफ दी एंग्लो- अमेरिकन सैटलमेंट प्रोपोजल"
इसू ।अफ्रीकन स्टडीज एसोसिएशन मैसेचुसेट्स। यू0 एस0 ए0
वाल्यूम नं0 11, नं 1, स्प्रिंग 1972

14- मुफुका, के0 न्यामायारो- "रोडेशिया इंटरनल सैटलमेंट : ए ट्रेजडी"
अफ्रीकन अफेयर्स ।आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस। लंदन,
वाल्यूम 78, नं0 313, अक्तूबर 1979

15- न्गारा, जॉन - "दी इंटरनल सेटलमेंट एंड दी जिम्बाब्वे रिवोलूशन"
दी अफ्रीकन कम्युनिस्ट ।इंकुलोको पब्लिकेशन। लंदन,
वाल्यूम, नं0 75, फोर्थ क्वार्टर 1978

16-"ए पालिसी फार रोडेशिया"
दी राउंड टेबल ।लंदन।,
नं0 222 , मार्च 1966

17- रैनडोल्फ, आर0 सी0एन- "दी बायर्ड सेटलमेंट"वर्ल्ड अफेयर्स -
।अमेरिकन पीस सोसायटी। यू0 एस0 ए0
वाल्यूम 141, नं0 1, समर 1978

17- साइथॉल, मैसीपुला - "रोडेशिया : एन स्सेसमेंट आफ दी
वायविलिटी आफ दी एंग्लो-अमेरिकन प्रोपोजल"
वर्ल्ड अफेयर्स ।अमेरिकन पीस सोसायटी। यू0 एस0 ए0
वाल्यूम 141, नं0 1, समर 1978

18- स्कूलर, रोबर्ट डी एंड पॉल रोबर्ट जे
" दी रोडेशियन एक्सपेरियंस अगेंस्ट दी आइडियल कंडीशन फार
इकानामिक सैंक्शन"
इंटरनेशनल स्टडीज ।नयी दिल्ली।, वाल्यूम 18, नं0 3, जुलाई-सितंबर 79

19- "दी इफेक्ट आफ सैंक्शन"
दी राउंड टेबल ।लंदन। नं0 226, अप्रैल 1967

20- टीसेम, मीक- "दी अप्रैल 1979 एलेक्शन इन जिम्बाब्वे - रोडेशिया"
अफ्रीकन एफेयर्स ।आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस। लंदन
वाल्यूम 78, नं0 313, अक्तूबर 1979

21- विंडरीच एलन - "दी एंग्लो -अमेरिकन इनेशियेटिव आन रोडेशिया :
एन इंटरीम सेटलमेंट"
दी वर्ल्ड टुडे ।लंदन।, वाल्यूम 25, जनवरी-दिसंबर 1979

22- विंडरीच,एलन - "रोडेशिया : दी रोड फ्राम लुआंडा टू जेनेवा"
दी वर्ल्ड टुडे ।रॉयल इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल एफेयर्स, लंदन।
वाल्यूम 33, नं0 3, मार्च 1977